- सोमनाथ-एक हजार वर्ष
- देश प्रथम, समरसता सर्वोपरि

- शिविर ख़त्म हुआ, सवाल शुरू हुए

प्रदूषण फैलाते छत्तीसगढ़ के मेडिकल हब

लाईफ वर्सिटी

वर्ष- 03 अंक -08 जनवरी 2026 मूल्य - 50 रू.

www.scgnews.in

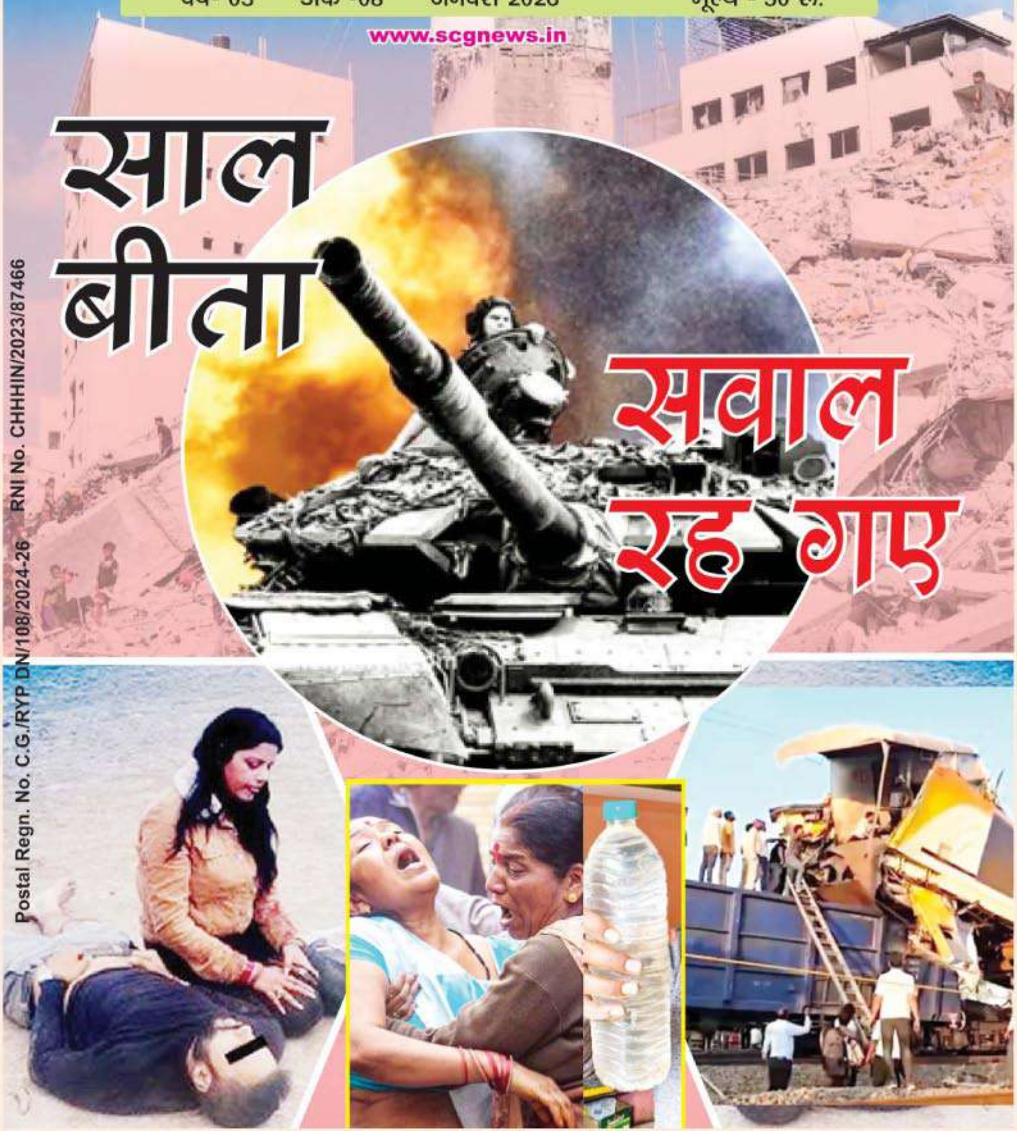

साल बीता

सवाल रह गए

Postal Regn. No. C.G./RYP DN/108/2024-26 RNI No. CHHHIN/2023/87466

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

मोदी संग बढ़त हे छत्तीसगढ़

पीएम आवास योजना

26 लाख
से अधिक परिवारों को पक्की छत देने वाले

महतारी वंदन योजना

70 लाख
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले

पीएम किसान सम्मान निधि

26 लाख
किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाले

तेंदूपत्ता संग्राहण दर ₹5500 मानक बोरा

13 लाख
संग्राहक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले

उद्यम क्रांति योजना

युवाओं को स्वरोज़गार के लिये **50% सब्सिडी** पर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाले

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

5.62 लाख
भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष **₹10,000** की आर्थिक सहायता देने वाले

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

37 लाख
महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाले

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना

37 हजार
से अधिक राम भक्तों को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराने वाले

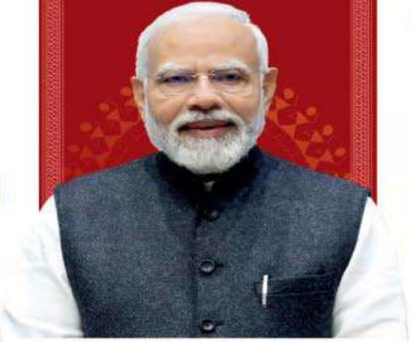

छत्तीसगढ़ में शांति, विश्वास और विकास का मार्ग हो रहा प्रशस्त

श्री विष्णु देव साय
मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

संवाद- 13621/163

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

◆◆◆

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

◆◆◆

सलाहकार मण्डल

डॉ अनिल गुप्ता	रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान	रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल	नई दिल्ली
प्रो तपन मोहन्ति	ओड़िसा

◆◆◆

सलाहकार (मीडिया मार्केटिंग एंड एआई)
भूपेन्द्र सिंग

◆◆◆

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स
मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979

◆◆◆

मध्यप्रदेश कार्यालय
अनामिका पाण्डेय
गोकुलधाम बेलौहान टोला,
सामान, रीवा मप्र

◆◆◆

प्रतिनिधि

अम्बुज अग्निहोत्री	जबलपुर
संजीव पाण्डेय	भोपाल
राजेश सिंह	बिलासपुर

◆◆◆

कानूनी सलाहकार
संजयेंदु पंड्या

◆◆◆

परिकल्पना
रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर

2025
साल बीता
2026
सवाल रह गए

03

7
सोमनाथ
एक हजार वर्ष

12
शिविर ख़त्म हुआ, सवाल शुरू हुए

16
देश प्रथम,
समरसता
सर्वोपरि

प्रदूषण फैलाते
छत्तीसगढ़ के
मेडिकल हब
24

23
पानी में
ज़हर,
फाइलों में
धूल

जय राम जी से G-RAM-G 10
छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा 14
छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की .. 18
कांगेर घाटी में मिली 'ग्रीन गुफा' 21
काश तिरंगा मेरा कफ़न होता 27

SCAN & PAY

UPI ID: 329944413263914@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार
में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सत्ती बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई
वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

हैप्पी न्यू ईयर नहीं, सच बोलने वाला साल

रात के ठीक बारह बजे, जैसे ही घड़ी की सुइयाँ एक-दूसरे से मिलीं, मोबाइल फ़ोन जगमगा उठे। व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम–हर स्क्रीन पर एक ही वाक्य तैरने लगा- "Happy New Year"। मानो ये दो शब्द लिख देने भर से पिछले साल की सारी थकान, टूटन, डर और असहायता अपने-आप धुल जाएगी। लेकिन ज़रा ठहरकर पूछना चाहिए–क्या बीता हुआ साल सच में हैप्पी था?

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

अगर ईमानदारी से देखें, तो यह साल खुशियों का नहीं, सहनशीलता का साल था। हमने जिया नहीं, झेला है। ख़ामोशी से, मजबूरी में और कई बार डर के साथ। हर नया साल कैलेंडर बदलकर आता है, व्यवस्था नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी जर्जर मकान पर नया रंग कर दिया जाए–बाहर चमक, भीतर वही दरारें।

नेताओं के लिए नया साल चुनावी रणनीति का कैलेंडर होता है, मीडिया के लिए टीआरपी का और आम आदमी के लिए–बस एक और साल गुज़र जाने का हिसाब। नौकरी तलाशता युवा, महँगाई से जूझता मध्यम वर्ग और दो वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ता श्रमिक–इनके जीवन में 'हैप्पी' शब्द कहीं दर्ज नहीं होता। लेकिन फिर भी हम सबको मुस्कुराना है, स्टोरी डालनी है, जश्न मनाना है–क्योंकि आज खुश रहना व्यक्तिगत भावना नहीं, सामाजिक बाध्यता बन चुका है।

अगर आप 31 दिसंबर की रात मुस्कुराते नहीं दिखे, अगर आपने 'न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन' नहीं लिखा, तो आप निगेटिव घोषित कर दिए जाते हैं। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ दुख व्यक्त करना भी अपराध है। लोग अंदर से टूटे हैं, लेकिन बाहर से हैप्पी दिखना ज़रूरी है। हर साल हम संकल्पों का झूठ दोहराते हैं–इस बार फिट रहेंगे, इस बार बेहतर इंसान बनेंगे, इस बार सच बोलेंगे। और जनवरी खत्म होते-होते ये संकल्प किसी पुराने अख़बार की तरह रद्दी में बदल जाते हैं। क्योंकि समस्या संकल्पों की कमी नहीं, ईमानदार आत्ममंथन की कमी है। जब तक हम खुद से सच नहीं बोलेंगे, कोई नया साल हमें नया नहीं बना सकता।

सिस्टम चाहता है कि आप उत्सव मनाएँ, सवाल नहीं। शुभकामनाएँ बाँटें, जवाब न माँगें। कई बार "Happy New Year" एक सांत्वना नहीं, एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है–ताकि असली मुद्दों पर बात ही न हो।

तो क्या नया साल सचमुच नया हो सकता है? हाँ–लेकिन शर्तों के साथ। जब हम अपने बच्चों को सिर्फ़ प्रतियोगिता नहीं, संवेदनशीलता सिखाएँ। जब ख़बरों को मनोरंजन नहीं, जिम्मेदारी समझें। जब धर्म, जाति और विचारधाराओं से ऊपर इंसान को इंसान की तरह देखें। और सबसे ज़रूरी–जब हम खुद से झूठ बोलना बंद करें।

इस साल अगर किसी को "Happy New Year" कहें, तो साथ में यह भी जोड़ दें–सच बोलिए, सवाल पूछिए और चुप्पी से समझौता मत कीजिए। क्योंकि खुशियाँ स्लोगन से नहीं आतीं, सच से आती हैं।

इसलिए इस बार शुभकामना बदलते हैं–

'सच बोलने वाला नया साल मुबारक हो।'

2025 साल बीता 2026 सवाल रह गए

2025 वह साल था जब दुनिया ने पहली बार सामूहिक रूप से यह स्वीकार किया कि अब संकट अपवाद नहीं, व्यवस्था बन चुके हैं। अब शांति कोई स्थिति नहीं, एक संघर्ष है। यह साल युद्धों का था,लेकिन उससे ज़्यादा यह साल मानसिक युद्धों का था। यह साल चुनावों का था, लेकिन उससे ज़्यादा लोकतंत्र की परीक्षा का था। यह साल तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार का था, लेकिन उससे ज़्यादा मानव विवेक की सीमाओं का था।

साल 2025 अब कैलेंडर के आख़िरी पन्नों में सिमट रहा है। यानि साल अब विदा ले रहा है। लेकिन यह साल किसी साधारण कैलेंडर वर्ष की तरह नहीं जा रहा। यह वर्ष इतिहास की किताबों में एक संक्रमण काल के रूप में दर्ज होगा। यह साल जा रहा है इतिहास के माथे पर एक गहरी लकीर बनाकर ।यह वह साल था जब दुनिया ने यह स्वीकार करना शुरू किया कि अब संकट अस्थायी नहीं , स्थायी हो चुके हैं। और समाधान नीतियों से नहीं, मानसिकताओं से निकलेंगे। 2025 वह साल था जब दुनिया ने पहली बार सामूहिक रूप से यह स्वीकार किया कि अब संकट अपवाद नहीं, व्यवस्था बन चुके हैं। अब शांति कोई स्थिति नहीं, एक संघर्ष है। यह साल युद्धों का था,लेकिन उससे ज़्यादा यह साल मानसिक युद्धों का था। यह साल चुनावों का था, लेकिन उससे ज़्यादा लोकतंत्र की परीक्षा का था। यह साल तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार का था, लेकिन उससे ज़्यादा मानव विवेक की सीमाओं का था।

साल 2025 वैश्विक राजनीति के लिए 'शब्दों' का साल रहा। यह वह दौर था जब एक बयान मिसाइल से ज़्यादा मारक साबित हुआ। दिसंबर 2025 में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए, तो दुनिया को किसी संयुक्त सैन्य समझौते की उम्मीद थी। लेकिन इतिहास में

'भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत शांति के पक्ष में है।' यह बयान न तो अमेरिका को खुश करने के लिए था, न ही रूस को संतुलित करने के लिए।

दर्ज हुआ एक वाक्य— 'भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत शांति के पक्ष में है।' यह बयान न तो अमेरिका को खुश करने के लिए था, न ही रूस को संतुलित करने के लिए। यह भारत की नई विदेश नीति का घोषणापत्र था— जहाँ नैरेटिव नहीं, नैतिकता तय करती है। यह वाक्य पश्चिम के लिए संदेश था कि भारत आपके दबाव में नहीं है। यह वाक्य रूस के लिए संदेश था— भारत आपका मोहरा नहीं है। और यह वाक्य ग्लोबल साउथ के लिए आश्वासन था— भारत अब नैतिक शक्ति (Moral Power) बनने की कोशिश में है। 2025 में भारत ने यह साफ कर दिया कि वह गुटनिरपेक्ष नहीं, विवेकनिरपेक्ष है।

नवंबर 2025- जापान की संसद में पहली बार सत्ता के शिखर पर एक महिला—सानए ताकाइची पहुंची। उन्होंने कहा—'अगर जापान के अस्तित्व पर संकट आया, तो हम सैन्य कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे।' यह वाक्य सिर्फ़ चीन के लिए नहीं था। यह पोस्ट-पैसिफिस्ट जापान की घोषणा थी। बीजिंग बौखला उठा। चीनी सागर में फाइटर जेट्स आमने-सामने आ गए। एशिया ने समझ लिया— अब शांति घोषणाओं से नहीं, ताकत के संतुलन से टिकेगी।

नवंबर 2025। डोनाल्ड ट्रंप—फिर से राष्ट्रपति बने । उन्होंने एक शब्द बैन कर दिया—"Indians"। तर्क था— यह ऐतिहासिक भूल है। लेकिन असल में यह पहचान की राजनीति थी— जहाँ भाषा, सत्ता का औज़ार बन जाती है। नेटिव अमेरिकन समुदाय भड़का। लिबरल खेमा उग्र हुआ। और ट्रंप मुस्कराते रहे। क्योंकि ट्रंप जानते हैं—सत्ता तर्क से नहीं, टकराव से मिलती है।

उधर तीन साल पुराना युद्ध जिसे 2025 में निर्णायक होना था। लेकिन हुआ उल्टा । यह साल थकान का साल बन गया। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को तबाह कर दिया। जब कोई नहीं जीत रहा था, फिर भी सब हार रहे थे। ड्रोन, मिसाइल, ब्लैकआउट। कीव, खारकीव, ओडेसा— हर शहर युद्ध की डायरी बन गया। यूक्रेन ने भी पलटवार किया। रूसी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले। अमेरिका और नाटो हथियार देते रहे। रूस, चीन-ईरान की ओर झुकता गया। मियामी, बर्लिन, जिनेवा— शांति वार्ताएँ हुईं। लेकिन भरोसा नहीं लौटा। 2025 वह साल था जब दुनिया ने समझा— Gen-Z सिर्फ़ इंस्टाग्राम नहीं है। सितंबर 2025 नेपाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया . कारण— 'राष्ट्रीय सुरक्षा।' बतलाया , नतीजा— राष्ट्रीय विस्फोट। युवाओं ने सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया। हिंसा भड़की। अंततः केपी ओली को जाना पड़ा। आज नेपाल में पूर्व CJI सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलनों ने नीतियाँ बदलीं। श्रीलंका में सत्ता बदली। फ्रांस-पोलैंड में चुनावी गणित बदला। 2025 ने स्पष्ट कर दिया— अब युवा सिर्फ़ भविष्य नहीं, वर्तमान हैं।

गाज़ा युद्ध नहीं था। वह मानवता का पोस्टमार्टम था। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं थीं। बच्चों के लिए दूध नहीं था। पानी और बिजली– लक्ज़री बन चुके थे। इज़राइल की बमबारी जारी रही। हमास रॉकेट चलाता रहा। और संयुक्त राष्ट्र बयान देता रहा। अरब देश चिंतित रहे। अमेरिका संतुलन साधता रहा। और गाज़ा– हर रोज़ थोड़ा–थोड़ा मरता रहा।

साल 2025 प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी याद किया याद किया जायेगा तो धार्मिक उदारता का अवसान के लिए भी । म्यांमार-थाईलैंड भूकंप — 1700 मौतें। हज़ारों घायल। इमारतें गिरीं। सड़कें टूटीं। सवाल यह — क्या दुनिया आपदाओं के लिए तैयार है? उत्तर—नहीं। 21 अप्रैल 2025। पोप फ्रांसिस नहीं रहे। उन्होंने कट्टरता को पाप कहा था। चर्च को मानवता के करीब लाने की कोशिश की थी। 8 मई को नए पोप बने— पोप लियो XIV (रॉबर्ट प्रेवोस्ट)। अब सवाल— क्या चर्च फिर रूढ़िवाद की ओर जाएगा? अंतरिक्ष में

दुनिया ने समझा— Gen-Z सिर्फ़ इंस्टाग्राम नहीं है।

NEPAL POLICE

पुना मारगेम
पुनर्वास से पुनर्जीवन

2025 में पहली बार राज्य ने नक्सलवाद से नहीं, नक्सलवाद ने राज्य से हार मानी।

बिलासपुर का बड़ा रेल हादसा– जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।

ISRO, NASA, SpaceX की दौड़। ने दिखा दिया कि 2025 में तकनीक बढ़ी है, लेकिन संवेदनशीलता नहीं।

अब बात छत्तीसगढ़ की जहां 2025 ने इतिहास का निर्णायक मोड़ रचा। जब लाल गलियारों से निकलकर राज्य ने विकास की दहलीज़ छुई। छत्तीसगढ़ जिसके बड़े हिस्से को सालों तक 'लाल गलियारा' कहकर डर के नक्शे पर टांगा गया। जहाँ सड़क बनाना चुनौती था, मोबाइल टावर लगाना जोखिम, और लोकतंत्र सिर्फ़ कागज़ों में मौजूद था। लेकिन 2025 में पहली बार राज्य ने नक्सलवाद से नहीं, नक्सलवाद ने राज्य से हार मानी। बसवाराजू। चलपति। हिड़मा। ये सिर्फ़ नाम नहीं थे, ये नक्सल नेटवर्क की रीढ़ थे। 2025 में सुरक्षाबलों ने इन शीर्ष नक्सली नेताओं को एक-एक कर खत्म किया। देश का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर भी इसी साल हुआ। रुपेश जैसे कई बड़े नाम सरकार के सामने हथियार डालने को मजबूर हुए।

यह साल राज्य के तीखी राजनीति के शुरुआत के लिए भी याद रहेगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा— जेल पहुँचे। कवासी लखमा पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप। जांच एजेंसियों की सक्रियता ने पूरे राज्य की राजनीति में भूकंप ला दिया। सरकार इसे 'भ्रष्टाचार पर कार्रवाई' कहती रही, विपक्ष इसे 'राजनीतिक बदले की राजनीति'। लेकिन सच यही था— 2025 में छत्तीसगढ़ की सियासत क्लीन चिट और क्लीन इमेज की लड़ाई बन गई।

यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती का साल था। राज्यभर में सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रम हुए। लेकिन यह जश्न सिर्फ़ उत्सव नहीं था— यह आत्ममंथन का मौका भी था। 25 साल बाद छत्तीसगढ़ खुद से पूछ रहा था— क्या हमने वह राज्य बना लिया, जिसका सपना देखा था? पहली बार 60वां अखिल भारतीय डीजी-आईजीपी सम्मेलन नवा रायपुर में हुआ। करीब 300 से अधिक शीर्ष पुलिस अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह। तीन दिन तक छत्तीसगढ़ देश की आंतरिक सुरक्षा का केंद्र बना रहा। यह राज्य के लिए प्रतीकात्मक नहीं, रणनीतिक उपलब्धि थी।

लेकिन 2025 में उपलब्धियों के साथ दुख भी आए। बिलासपुर का बड़ा रेल हादसा— जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। और छत्तीसगढ़ ने अपने महान साहित्यकार विनोद शुक्ल को खो दिया। यह साल खुशी और शोक— दोनों की यादें छोड़ गया ।अगर आने वाले वर्षों में कोई पूछेगा कि 2025 किस बात के लिए याद किया जाएगा, तो जवाब किसी एक घटना में नहीं मिलेगा —वह मिलेगा वक्फ से हसदेव तक,पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर तक,और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से दिल्ली की जहरीली हवा तक फैले उस राष्ट्रीय तनाव में जिसे हमने खबरों में जिया, लेकिन समझने से अक्सर चूक गए। 2025 का पहला बड़ा सियासी विस्फोट वक्फ संशोधन विधेयक था। सरकार इसे प्रशासनिक पारदर्शिता कहती रही, विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे संवैधानिक असुरक्षा। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम। एक आतंकी हमला — निर्दोष लोग, शहीद सुरक्षाकर्मी और टूटा हुआ

पहलगाम- एक आतंकी हमला

सबसे बड़ा मौन कोई था, तो वह था हसदेव अरण्य

विश्वास। सवाल जो गायब रहे- आतंकी घुसपैठ कैसे हुई? खुफिया तंत्र कहाँ चूका? स्थानीय युवाओं की भूमिका क्यों बढ़ रही है? शहादत का सम्मान हुआ,लेकिन सिस्टम की समीक्षा नहीं।

इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर सरकार, राज्यपालों और जांच एजेंसियों पर असामान्य रूप से कड़ी टिप्पणियाँ कीं। यह सिर्फ़ कानूनी घटनाएँ नहीं थीं, ये संकेत थे कि संवैधानिक संतुलन डगमगा रहा है। मीडिया ने इसे 'टकराव' की तरह दिखाया, लेकिन यह असल में चेतावनी थी। एक लोकतंत्र में जब अदालत को बार-बार याद दिलाना पड़े कि संविधान क्या कहता है, तो समस्या फैसलों में नहीं, नियत में होती है। 2025 में ED, CBI, IT — नाम नहीं, ब्रांड बन गए। छापे, गिरफ्तारियाँ, जमानत बहस — सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन सवालों की सूची लंबी रही- कार्रवाई का समय चुनावों से क्यों मेल खाता है?,सत्तापक्ष पर वही पैमाना क्यों लागू नहीं? न्याय प्रक्रिया सज़ा से पहले ही सज़ा क्यों बन रही है? जांच एजेंसियाँ कानून के लिए बनी थीं, पर 2025 में वे संदेह के कटघरे में रहीं।

अगर 2025 का सबसे बड़ा मौन कोई था, तो वह था हसदेव अरण्य। पेड़ कटे, आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के लिए यह मुद्दा कभी भी पहलगाम जितना 'हॉट' नहीं बन सका। क्योंकि- यहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता , यहाँ राष्ट्रवाद नहीं बिकता , यहाँ सिर्फ़ जीवन बचाने की बात होती है और जीवन, आज की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होता। तमनार की जनसुनवाई सिर्फ़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, वह एक सवाल थी— 'क्या विकास का मतलब गाँव की सहमति के बिना आगे बढ़ना है?' ग्रामीण सड़क पर थे, कॉरपोरेट रिपोर्ट में थे, और मीडिया — कहीं और। 2025 ने साफ़ कर दिया कि विकास की भाषा और लोकतंत्र की भाषा अब एक जैसी नहीं रहीं। दिल्ली की हवा 2025 में भी ज़हरीली रही। नए आंकड़े, पुराने बयान, वही मास्क। हर सरकार आई, गई, लेकिन हवा वहीं रुकी रही। दिल्ली प्रदूषण इस बात का प्रतीक बन गया कि हम समस्या पहचानते हैं, समाधान टालते हैं और आदत बना लेते हैं। को याद किया जाएगा क्योंकि ,कानून सवालों में था , सुरक्षा भावनाओं में न्याय चेतावनी में, विकास टकराव में और पर्यावरण उपेक्षा में यह साल बताएगा कि भारत की असली लड़ाई सीमाओं पर नहीं, प्राथमिकताओं में है।

> “
> 2025 का सबसे बड़ा सबक है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज़्यादा। जहाँ सत्ता को ताकतवर होने से ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। जहाँ दुनिया को यह तय करना होगा कि वह हथियारों में निवेश करेगी या इंसानियत में।
> ”

छत्तीसगढ़ ने अपने महान साहित्यकार विनोद शुक्ल को खो दिया।

अब जब साल 2025 विदा ले रहा है। तो यह किसी अख़बार की पुरानी कटिंग की तरह नहीं जाएगा। यह साल हमारे समय की मानसिक फाइल बनकर रहेगा। 2025 ने हमें यह नहीं बताया कि कौन जीता और कौन हारा। इसने यह दिखाया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं—और क्यों। शायद 2025 का सबसे बड़ा सबक है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज़्यादा। जहाँ सत्ता को ताकतवर होने से ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। जहाँ दुनिया को यह तय करना होगा कि वह हथियारों में निवेश करेगी या इंसानियत में। साल 2025 जा रहा है। लेकिन इसके सवाल हमारे साथ रहेंगे। और शायद इतिहास एक दिन लिखेगा— 2025 वह साल था जब दुनिया ने रुककर सोचना शुरू किया।

अब जब कैलेंडर बदल रहा है तो उम्मीद है सोच भी बदलेगी। नया साल सिर्फ़ तारीख़ों का नहीं, दृष्टि का परिवर्तन हो। जहाँ सवाल दबाए न जाएँ, संवाद बचे रहें। जहाँ विकास का मतलब सिर्फ़ ऊँची इमारतें नहीं, बल्कि ऊँचा विवेक हो। नव वर्ष 2026 छत्तीसगढ़ को डर से नहीं, दिशा से पहचान दे। भारत को भीड़ से नहीं, बुद्धि से नेतृत्व करने का साहस दे। और दुनिया को युद्ध से नहीं, मानवता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।

।। सोमनाथ।।

एक हजार वर्ष

आस्था, स्वाभिमान और भारत की अमर आत्मा

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

सोमनाथ... ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है...'सौराष्ट्रे सोमनाथं च...'यानि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है-

'सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥'

अर्थात्, सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है।

दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था।

वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

> सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनर्निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन

राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दु:ख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है।

हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा था। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है।

1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुन: जीवंत किया।

महमूद गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं की भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है, कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है।

ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे, वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की।

उन्होंने कहा, दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे।

इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं, और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार बार नष्ट किए गए, और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त। पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।

ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दीवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंतत: 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।

उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना

राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया।

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख के.एम. मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य, विशेष रूप से उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटरनल', अवश्य पढ़ी जानी चाहिए।

जैसा कि मुंशी जी की पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट होता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही।

अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है।

इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वो हमारे इनोवेटिव युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है।

अनादि काल से सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है। सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहां आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा,

भवबीजा-ुरजनना रागाद्या: क्षयमुपगता यस्य।

अर्थात्, उस परम तत्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं। जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं।

आज भी दादा सोमनाथ के दर्शन से ऐसी ही अनुभूति होती है। मन में एक ठहराव आ जाता है, आत्मा को अंदर तक कुछ स्पर्श करता है, जो अलौकिक है, अव्यक्त है।

1026 के पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा है।

अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये विश्वास का वो स्वर है, जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है।

अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है।

जय राम जी से G-RAM-G आस्था, अल्गोरिदम और सत्ता की नई राजनीति

भारतीय राजनीति अब नारों से नहीं, मॉडलों से चल रही है। 'जय राम जी' एक ऐसा शब्द है—जो मंदिर की घंटी से निकलकर मतदान केंद्र की मशीन तक पहुँचा। लेकिन अब वही नारा एक नए अवतार में दिख रहा है— G-RAM-G। यह बदलाव सिर्फ़ भाषा का नहीं है, यह बदलाव है राजनीतिक दर्शन का।

कल तक 'जय राम जी' भावनात्मक पहचान था, आज G-RAM-G प्रशासनिक पहचान बन रहा है। भाजपा इसे 'ग्राम स्वराज का डिजिटल संस्करण' बताती है, लेकिन विपक्ष इसे 'ग्राम पर निगरानी का नया औज़ार' मान रहा है। तो सवाल है—G-RAM-G है क्या? काम कैसे करता है? और इससे किसे डर लग रहा है?

'जय राम जी' भाजपा के लिए केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं थी। यह एक सांस्कृतिक संकेत था— जिसके सहारे पार्टी ने पहचान (Identity) की राजनीति को स्थायित्व दिया।

राम— मर्यादा का प्रतीक थे , त्याग का प्रतीक थे , व्यवस्था के भीतर संघर्ष का प्रतीक थे 7 लेकिन राजनीति में आते-आते राम भावना बन गए, और भावना मत। भाजपा ने इस भावना को संविधान के पन्नों से ज़्यादा जनमानस के अवचेतन में उतारा। यहीं से शुरू हुआ धर्म से डिसिप्लिन और आस्था से आज्ञाकारिता का सफ़र।

और अब— G-RAM-G यह कोई नारा नहीं, यह एक राजनीतिक मॉडल है।

- G- Governance (शासन)
- RAM - Resources, Algorithm, Management
- G - Growth (विकास) का

यानी— अब राजनीति मंदिर के चबूतरे से नहीं, डेटा सेंटर से चल रही है। अब वोटर— भक्त नहीं, यूज़र है। गाँव— संस्कृति नहीं, यूनिट है। अब समस्या— संवेदना नहीं, डैशबोर्ड है। भाजपा ने भावनाओं को छोड़ा नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया।

- **राम मंदिर** - सांस्कृतिक कैपिटल
- **लाभार्थी योजना** - आर्थिक अनुशासन
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** - निगरानी और मैपिंग
- **पंचायत से संसद तक** - डेटा-ड्रिवन कंट्रोल

यही है G-RAM-G मॉडल— जहाँ गाँव को लाभार्थी सूची में बदला गया , जाति को डेटा पॉइंट में और असहमति को आउटलायर में।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार G-RAM-G मॉडल दरअसल छत्तीसगढ़ की ग्रामीण राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है—जहाँ मनरेगा, कृषि, पलायन और पंचायत, सबको एक प्रशासनिक एल्गोरिदम में पिरोने की कोशिश की गई है। सवाल यह है—

क्या लोकतंत्र अल्गोरिदम से चल सकता है? जब—समस्या का समाधान ऐप से होगा ,संवाद की जगह सर्वे होगा , आलोचना को एंटी-डेटा कहा जाएगा तो फिर— लोकतंत्र बचेगा या सिर्फ़ मैनेजमेंट सिस्टम?

खेती के मौसम में काम बंद-नीति की समझ या ज़मीनी अनदेखी?

G-RAM-G का सबसे विवादास्पद पहलू

125 दिन का रोजगार- राहत या भरोसे की पुनर्परीक्षा?

मुख्यमंत्री साय का सबसे बड़ा दावा है–ग्रामीण परिवारों को 100 नहीं, 125 दिन का रोजगार मिलेगा । यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब महंगाई, अनिश्चित खेती और सीमित विकल्पों ने गांव की अर्थव्यवस्था को लगातार कमजोर किया है। सरकार कहती है कि मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर होगा और देरी पर पेनल्टी लगेगी। श्रमिको को अतिरिक्त पैसा मिलेगा , यह सुनने में श्रमिक हितैषी लगता है। लेकिन ग्रामीण भारत जानता है–समस्या नियमों की नहीं, नीयत और अमल की होती है। अगर भुगतान समय पर हुआ, तो यह योजना सिर्फ़ रोजगार नहीं देगी, भरोसा भी लौटाएगी। और अगर नहीं हुआ, तो यह पुराने घावों को और गहरा करेगी।

है—खेती और कटाई के समय योजना के तहत काम रोकना। सरकार का तर्क है कि इससे किसान-मज़दूर अपने खेतों पर ध्यान देंगे और मनरेगा खेती का विकल्प नहीं बनेगा। काग़ज़ पर यह संतुलन दिखता है। लेकिन गांव कोई एक्सेल शीट नहीं है। हर फसल, हर खेत, हर मज़दूर की ज़रूरत अलग होती है। अगर इस नीति में स्थानीय लचीलापन नहीं हुआ, तो यही संतुलन नई असमानता बन सकता है।

पलायन रोकने का दावा- अधूरा सच

सरकार मानती है कि स्थानीय रोजगार से पलायन रुकेगा। यह तर्क आधा सही है। पलायन सिर्फ़ रोज़गार का सवाल नहीं—वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा होता है। अगर G-RAM-G इन सभी आयामों से नहीं जुड़ता, तो यह योजना पलायन को रोकने का नहीं, सिर्फ़ टालने का साधन बनकर रह जाएगी।

विकास के चार स्तंभ- दिशा सही, दृष्टि अधूरी ?

जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, कृषि आधारित काम और पशुपालन—ये चार प्राथमिक क्षेत्र बताते हैं कि सरकार रोजगार को सिर्फ़ गड्ढा खोदने तक सीमित नहीं रखना चाहती। यह एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन सवाल यह है—क्या पंचायतें इन प्राथमिकताओं को तय करेंगी, या डैशबोर्ड तय करेगा कि किस गांव को क्या चाहिए?

PM गति शक्ति और G-RAM-G: योजना नहीं, सिस्टम

जब सरकार कहती है कि G-RAM-G को PM गति शक्ति से जोड़ा जाएगा, तो यह साफ़ हो जाता है कि यह योजना नहीं, एक सिस्टम है। आर सिस्टम को फ़ायदा है—समन्वय, डेटा और गति से जबकि सिस्टम का खतरा है—संवेदना के गायब हो जाने से।

राजनीति का असली तनाव

भाजपा इसे 'ग्राम स्वराज का डिजिटल संस्करण' कहती है। कांग्रेस इसे 'ग्राम पर निगरानी का औज़ार' मानती है। गांधी नाम हटाये जाने से आपत्ति है। गांधी नाम का टकराव सिर्फ़ सत्ता का नहीं बल्कि शासन की दो अवधारणाओं का है। G-RAM-G उस राजनीति को अप्रासंगिक करता है, जहाँ योजना नेता दिलाता था, सिस्टम नहीं। और यही कारण है कि कांग्रेस का विरोध अस्तित्वगत है, सिर्फ़ राजनीतिक नहीं। G-RAM-G का सबसे संवेदनशील पक्ष है—डेटा। किस गांव को कितना मिला, किस जाति को क्या मिला, कौन लाभार्थी है—यह सब अब सिस्टम जानता है। सवाल यह है कि इस डेटा का मालिक कौन है? और इसका उपयोग सिर्फ़ विकास के लिए होगा, या राजनीति के लिए भी?

डेटा बनाम लोकतंत्र

'जय राम जी' में कम से कम भावना थी। G-RAM-G में सिर्फ़ एफ़िशिएंसी है। भावना गलती कर सकती है, लेकिन इंसान रहती है। अल्गोरिदम गलती नहीं करता, लेकिन निर्दयी होता है। भाजपा की नीति का यह नया चेहरा तेज़ है, स्मार्ट है, लेकिन सवाल पूछने वालों के लिए बेहद असहज भी। अगर— राम केवल प्रतीक थे और G-RAM-G केवल सिस्टम है तो फिर बीच में जनता कहाँ है? क्या वह सिर्फ़— डेटा है, लाभार्थी है, या फिर एक दिन डिलीट होने वाला यूज़र? यही सवाल जय राम जी से G-RAM-G तक की यात्रा का सबसे असहज सत्य है।

G-RAM-G न पूरी तरह सही है, न पूरी तरह गलत। यह विकास का औज़ार भी है और नियंत्रण की तकनीक भी। सवाल सरकार से कम, समाज से ज़्यादा है— क्या हम सिर्फ़ लाभार्थी बनकर खुश रहेंगे, या नागरिक बने रहने की ज़िद करेंगे? 'जय राम जी' एक भावना थी। G-RAM-G एक प्रणाली है। लेकिन लोकतंत्र न भावना से चलता है, न सिर्फ़ प्रणाली से— वह चलता है सवाल पूछने की आज़ादी से। और यही सवाल इस पूरी नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है।

प्रशासनिक खर्च 9%: निगरानी या विस्तार?

प्रशासनिक व्यय को 6 से 9 प्रतिशत करना बताता है कि सरकार निगरानी और तकनीक पर भरोसा कर रही है। लेकिन ग्रामीण भारत पूछता है—यह पैसा फील्ड में जाएगा या फ़ाइलों में?

महिला समूह- भागीदारी या प्रतीक ?

महिला स्व-सहायता समूहों को योजना से जोड़ना सही दिशा में कदम है। लेकिन सवाल यह है—क्या महिलाएँ निर्णय का हिस्सा होंगी, या सिर्फ़ क्रियान्वयन का?

शिविर ख़त्म हुआ, सवाल शुरू हुए

पाँच दिवसीय मेगा हेल्थ चेकअप कैंप केवल एक स्वास्थ्य आयोजन नहीं था। यह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सक्रियता, प्रशासन की सीमाएँ और राज्य की स्वास्थ्य नीति—तीनों का एक साथ सार्वजनिक परीक्षण था।

नरेन्द्र पाण्डेय

रायपुर के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में दिसंबर के तीसरे सप्ताह आयोजित पाँच दिवसीय मेगा हेल्थ चेकअप कैंप केवल एक स्वास्थ्य आयोजन नहीं था। यह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सक्रियता, प्रशासन की सीमाएँ और राज्य की स्वास्थ्य नीति—तीनों का एक साथ सार्वजनिक परीक्षण था। स्थानीय विधायक राजेश मूणत द्वारा आयोजित यह शिविर अपने पैमाने, संसाधनों और सामाजिक सहभागिता के कारण छत्तीसगढ़ के शहरी स्वास्थ्य आयोजनों में एक संदर्भ-बिंदु बन गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा उद्घाटन और राज्यपाल रोमन डेका द्वारा समापन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल एक क्षेत्रीय पहल नहीं थी—बल्कि सत्ता के शीर्ष स्तर ने भी इसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से मान्यता दी।

विधायक की राजनीतिः घोषणा नहीं, संगठन

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि विधायक राजेश मूणत ने इस शिविर के माध्यम से घोषणात्मक राजनीति के बजाय संगठनात्मक सेवा मॉडल को सामने रखा। पाँच दिन तक 10-12 हजार लोगों की उपस्थिति, ऑनलाइन-ऑफलाइन पंजीयन, तीन-स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था, समाज की भागीदारी और बहु-पद्धति चिकित्सा—यह सब केवल सरकारी आदेश से संभव नहीं होता। इसके पीछे निरंतर निगरानी, स्थानीय नेटवर्क और राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है।

मूणत का यह छठवाँ मेगा हेल्थ कैंप था—यह तथ्य बताता है कि यह कोई चुनावी तात्कालिकता नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास है। आज की राजनीति में जहाँ जनप्रतिनिधि 'काम' से अधिक 'कथन' पर निर्भर दिखते हैं, वहाँ इस तरह का आयोजन प्रशंसा का पात्र है। लेकिन यहीं से नीति का सवाल शुरू होता है

अगर एक विधायक अपने स्तर पर इतना कर सकता है, तो राज्य की स्वास्थ्य नीति क्या कर रही है? यह शिविर राज्य सरकार के लिए अवसर था—

- यह समझने का कि लोग नियमित अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे
- यह जानने का कि सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की माँग कहाँ और क्यों है
- और यह देखने का कि आयुष्मान जैसी योजनाएँ ज़मीनी स्तर पर कैसे काम कर रही हैं

समाज ने साथ दिया, नीति ने दूरी रखी

शिविर की सफलता में समाज की भूमिका निर्णायक रही— सामाजिक संस्थाएँ, स्वयंसेवक, छात्र, स्थानीय डॉक्टर। लेकिन नीति का काम समाज पर निर्भर होना नहीं, समाज को सहारा देना होता है। राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि वह स्वास्थ्य को नेताओं की व्यक्तिगत पहल के भरोसे छोड़ेगी, या उसे संस्थागत अधिकार बनाएगी।

रायपुर का मेगा हेल्थ कैंप इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इसने दो तस्वीरें एक साथ दिखाईं– एक, एक विधायक की इच्छाशक्ति और संगठन क्षमता की। दूसरी, राज्य की स्वास्थ्य नीति की सीमाओं की। विधायक की प्रशंसा बनती है–बिना किसी लेकिन के। लेकिन सरकार और नीति के लिए यह शिविर प्रशंसा–पत्र नहीं, चेतावनी–पत्र है।

क्योंकि लोकतंत्र में सेवा किसी व्यक्ति का गुण हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरत किसी व्यवस्था की ज़िम्मेदारी होती है। अब सवाल यह नहीं कि शिविर कितना बड़ा था। सवाल यह है– क्या राज्य सरकार इस पहल को नीति में बदलने का साहस दिखाएगी, या इसे भी एक सफल आयोजन की फ़ाइल में बंद कर देगी?

लेकिन व्यवहार में यह अवसर नीति-निर्माण के बजाय इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित रह गया।

भाजपा सरकार और स्वास्थ्य का राजनीतिक मॉडल

भाजपा सरकार ने हमेशा डिलीवरी आधारित गवर्नेंस की बात की है। सड़क, बिजली, आवास, राशन—इन क्षेत्रों में यह मॉडल दिखाई भी देता है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह मॉडल अब भी व्यक्ति-आधारित पहलों पर निर्भर दिखता है, न कि संस्थागत नीति पर। रायपुर का यह शिविर सवाल उठाता है—

क्या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी 'नेतृत्व-आधारित राहत' पर टिकी है, या 'संरचना-आधारित समाधान' की ओर बढ़ रही है? जब हजारों लोग पाँच दिन के लिए एक अस्थायी शिविर में इलाज के लिए उमड़ते हैं, तो यह केवल शिविर की सफलता नहीं—यह संकेत है कि स्थायी सिस्टम भरोसा नहीं जगा पा रहा।

इंटीग्रेटेड हेल्थः नीति में क्यों नहीं?

इस शिविर की एक बड़ी उपलब्धि थी— एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक साथ होना। यह वही इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉडल है, जिसकी बात नीति दस्तावेज़ों में वर्षों से होती रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह पाँच दिन के लिए संभव है, तो 365 दिन क्यों नहीं?

क्या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई स्पष्ट रोडमैप है, जिसमें जिला अस्पतालों में आयुष, एलोपैथी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ एकीकृत रूप से उपलब्ध हों? अगर नहीं, तो रायपुर का यह शिविर नीति के लिए चेतावनी है—प्रेरणा नहीं।

आयुष्मान-कवरेज बनाम भरोसा

आयुष्मान भारत योजना को इस शिविर में प्रमुखता से पेश किया गया। लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि

- पैकेज से बाहर की बीमारियों के लिए क्या रणनीति है
- रेफरल के बाद मरीज की वित्तीय सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी

यह नीति का प्रश्न है, आयोजन का नहीं। और यही वह बिंदु है जहाँ राज्य सरकार को स्पष्टता दिखानी होगी।

राजनीतिक श्रेय और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी

इस शिविर ने एक दिलचस्प राजनीतिक स्थिति पैदा की। एक ओर एक विधायक की सराहनीय सक्रियता, दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की नीति-स्तरीय चुप्पी। राजनीतिक रूप से देखें तो भाजपा सरकार के लिए यह दोधारी तलवार है। अगर इसे मॉडल माना जाता है, तो सवाल उठेगा—यह मॉडल अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? और अगर इसे अपवाद माना जाता है, तो यह स्वीकारोक्ति होगी कि सिस्टम सामान्य परिस्थितियों में विफल है।

सशक्त महिलाएं, सक्षम युवा– छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को यदि बीते दो वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने 'कल्याण' और 'क्षमता निर्माण'—इन दोनों ध्रुवों पर एक साथ काम किया है। एक ओर महिला एवं बाल विकास विभाग ने समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की मुख्यधारा से जोड़ा, तो दूसरी ओर उच्च शिक्षा विभाग ने ज्ञान, शोध और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के माध्यम से भविष्य की नींव मजबूत की। यही समन्वय छत्तीसगढ़ को एक समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल की ओर ले जाता है।

कल्याण से आत्मनिर्भरता की ओर

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के अनुसार, बीते दो वर्षों में विभाग ने केवल योजनाएं लागू नहीं कीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों के जीवन में ठोस सामाजिक बदलाव का आधार तैयार किया है। महतारी वंदन योजना इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। 69 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष सहायता केवल आर्थिक संबल नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की निर्णय क्षमता और सामाजिक हैसियत को मजबूत करने वाला कदम है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं पारिवारिक और आर्थिक फैसलों में स्वतंत्र भूमिका निभा रही हैं।

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता देकर छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि बताती है कि मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर राज्य की प्रशासनिक प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में भी राज्य ने निर्णायक प्रगति की है। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 तक स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 19 लाख से अधिक हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार की आपूर्ति—वह भी महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी से—पारदर्शिता और गुणवत्ता का उदाहरण है।

महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने जमीनी स्तर पर भरोसे का तंत्र खड़ा किया है। दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर और बाल संरक्षण सेवाओं में छत्तीसगढ़ का अग्रणी राज्यों में शामिल होना इस बात का संकेत है कि नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी कम हुई है।आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, ई-भर्ती पोर्टल और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसी पहलों ने विभागीय कार्यप्रणाली को आधुनिक और संवेदनशील दोनों बनाया है।

ज्ञान से रोजगार तक की तैयारी

यदि महिला एवं बाल विकास विभाग सामाजिक सुरक्षा की नींव है, तो उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की भविष्य की अर्थव्यवस्था का इंजन बनता दिख रहा है। वर्ष 2023-24 में 1212.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1822.75 करोड़ रुपये का बजट—लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि—यह दर्शाता है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को केवल खर्च नहीं, बल्कि निवेश मान रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन प्रदेश के 09 में से 07 विश्वविद्यालयों में किया जा चुका है। इसके अंतर्गत 42 स्किल एवं एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स, 108 जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स, और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करना—यह सब शिक्षा को स्थानीय, वैश्विक और व्यावहारिक बनाने की दिशा में कदम हैं। रुसा कार्यालय में गठित रिसर्च क्वालिटी इंडस्ट्री-अकादमिक कोलैबोरेशन सेल उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच सेतु का काम कर रहा है।

शिक्षक संवर्ग में पदोन्नतियां, सीधी भर्तियां और वेतनमान उन्नयन से शैक्षणिक वातावरण को स्थिरता मिली है। 595 प्राध्यापक पदों पर भर्ती, अतिथि व्याख्याता नीति-2024 और ई-ऑफिस प्रणाली ने प्रशासनिक सुगमता और पारदर्शिता को बढ़ाया है। नैक मूल्यांकन में भी राज्य की स्थिति सुदृढ़ हुई है—200 से अधिक महाविद्यालयों और 05 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन, तथा कई संस्थानों को 'A' और 'A+' ग्रेड मिलना गुणवत्ता की ओर बढ़ते कदम का संकेत है।

पीएम-उषा योजना के तहत बस्तर स्थित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये का अनुदान, तथा अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मिला सहयोग—यह स्पष्ट करता है कि राज्य बहु-संकाय और शोध आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

आगामी कार्ययोजनाः शिक्षा + कौशल + रोजगार

आने वाले तीन वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन के तहत गुड गवर्नेंस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर केंद्रित 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राज्य रिसर्च एवं इनोवेशन योजना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, और नंदी फाउंडेशन-नेसकॉम जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग—ये सभी कदम शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में हैं। चार वर्षीय बी.एड., आई.टी.ई.पी., बी.पी.एड. जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन और कौशल/उद्यमिता आधारित पाठ्यचर्याएं राज्य के युवाओं को डिग्री से आगे करियर की ओर ले जाती हैं।

महिला एवं बाल विकास और उच्च शिक्षा—ये दोनों विभाग मिलकर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा से सशक्तिकरण और ज्ञान से रोजगार की एक साझा कहानी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की विकास दृष्टि केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की संरचना बदलने का प्रयास है।छत्तीसगढ़ आज उस मोड़ पर खड़ा है, जहां कल्याणकारी राज्य और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था एक-दूसरे के पूरक बन रहे हैं—और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

एआई टेक्नालॉजी के उपयोग से कम एफर्ट में होगा ज्यादा काम:आयुक्त डॉ. रवि मित्तल

जनसंपर्क अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला

मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल ने कहा कि जनसंपर्क अधिकारी एक्सक्लूजिव स्टोरी तैयार करें और इसके व्यापक प्रचार के लिए मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की स्टोरी नेशनल और स्टेट लेवल पर प्रकाशित होगी, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जाएगा। आयुक्त डॉ. मित्तल नवा रायपुर स्थित संवाद के ऑडिटोरियम में जनसम्पर्क की नई चुनौतियां विषय पर जनसम्पर्क अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला में उक्त बातें कहीं।

आयुक्त डॉ. मित्तल ने कहा कि वर्तमान दौर में जनसंपर्क में सूचना एवं जनसंपर्क का माध्यम बदल रहे हैं। नए-नए तकनीक आ रहे हैं, जनसंपर्क अधिकारियों को भी उन तकनीकों का उपयोग कर अपने कार्य को प्रमाणिक, बेहतर और समय सीमा में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया का बखूबी उपयोग करना है, ताकि शासन की फैसलों को जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए अधिकारियों को नए टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारिता स्कूल-कॉलेजों के बच्चों को भी जनसंपर्क विभाग में इंटरशीप का अवसर देने पर बल दिया।

जनसंपर्क के लिए प्रभावी संवाद सबसे बड़ी आवश्यकता

उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों में अपर संचालक जवाहरलाल दरियो, संजीव तिवारी, उमेश मिश्रा, आलोक देव ने जनसेवा में स्पष्ट, सरल और समयबद्ध संवाद की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनसंपर्क के लिए प्रभावी संवाद सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रतिभागियों को दो दिनों तक चलने वाले सत्रों की रूपरेखा और अपेक्षाओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य समाचार लेखन, टेलीविजन सहभागिता और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जनसंपर्क को अधिक सशक्त, आधुनिक, संवेदनशील और उन्मुखी बनाना है।

मीडिया से संतुलित और समयबद्ध संवाद की आवश्यकता

कार्यशाला के प्रथम दिवस की शुरुआत पाठक-अनुकूल लेखन सरकारी समाचार को आकर्षक बनाना विषयक सत्र से हुई, जिसमें दैनिक भास्कर के संपादक शिव दुबे ने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सरकारी आदेशों और सूचनाओं से जनता से जुड़ी मुख्य बात को पहचानने, सरल और सुबोध भाषा के प्रयोग, प्रभावी हेडलाइन एवं लीड पैराग्राफ लिखने की जानकारी दी। साथ ही, प्रेस विज्ञप्ति की संरचना, उपयुक्त उद्धरणों के प्रयोग तथा संकट के समय मीडिया से संतुलित और समयबद्ध संवाद की आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा की।

द्वितीय सत्र में आकाशवाणी के समाचार संपादक विकल्प शुक्ला ने टेलीविजन मीडिया की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों को विजुअल स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करने, टीवी कवरेज के लिए आवश्यक तत्वों, कैमरे पर संक्षिप्त बाइट लेने और फैक्ट शीट के महत्व की जानकारी दी।

तीसरे सत्र में सोशल मीडिया और एआई टूल्स के उपयोग पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और एआई विशेषज्ञ राकेश साहू ने एआई डिजिटल टूल्स का उपयुक्त उपयोग कर फोटो, वीडियो एडिटिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया।

अंतिम सत्र में जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल के सेवानिवृत्त संचालक लाजपत आहूजा ने पीआर टूल बॉक्स, स्टेकहोल्डर प्रबंधन तथा आपातकालीन संचार (क्राइसिस कम्युनिकेशन) से जुड़े तुरंत उपयोग योग्य उपकरणों की जानकारी दी। कार्यशाला में राज्यभर से आए जनसंपर्क अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

देश प्रथम, समरसता सर्वोपरि

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष **अमरजीत सिंह छाबड़ा** से नरेन्द्र पाण्डेय की विशेष चर्चा

देश की राजनीति, समाज और प्रशासन के बीच आज सबसे बड़ा प्रश्न 'नेरेटिव' का है। किस दिशा में समाज को ले जाया जा रहा है? पहचान की राजनीति के बीच राष्ट्रीय एकता कैसे बचे? इन्हीं सवालों के केंद्र में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा का दृष्टिकोण "Nation First" यानी देश प्रथम की स्पष्ट रेखा खींचता है।

'लाईफवर्सिटी' के सम्पादक नरेन्द्र पाण्डेय से हुई इस विस्तृत चर्चा में चावला न सिर्फ अपने कार्यकाल की प्राथमिकताएँ बताते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण का अर्थ तुष्टिकरण नहीं, बल्कि समान अवसर और राष्ट्रीय समरसता है।

पदभार का पहला संदेश - देश प्रथम

छाबड़ा कहते हैं–'देश भर में जिस तरह से एक नेरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है, उसमें अल्पसंख्यकों की भूमिका बड़ी हो जाती है। राष्ट्रीय एकता को लेकर, देश प्रथम को लेकर । इसलिए मेरा पहला और आख़िरी मंत्र है–देश प्रथम।'

> अल्पसंख्यक कल्याण का अर्थ तुष्टिकरण नहीं, बल्कि समान अवसर और राष्ट्रीय समरसता है।

पदभार ग्रहण के दिन ही यह भाव स्पष्ट कर दिया गया। उसी समय ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा त्वरित घटनाक्रम चल रहा था। आयोग के मंच से राष्ट्रगीत, देशभक्ति और सभी धर्मों की सहभागिता के साथ यह संदेश दिया गया कि आयोग किसी एक समुदाय का नहीं, राष्ट्र की समरस चेतना का प्रतिनिधि है।

साधु-संतों की सुरक्षा से प्रशासन तक

जैन समाज के साधु-संतों के विहार, चातुर्मास और पर्युषण पर्व के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया।

छाबड़ा बताते हैं– 'हमने तत्कालीन मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखा। उसके बाद सभी ज़िलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी हुए।'

इसके साथ ही जैन समाज के प्रमुख मंदिरों को अधिकृत पत्र उपलब्ध कराए गए, ताकि मंगल विहार के दौरान साधु-संतों को प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

गौरवशाली इतिहास की वापसी

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को आयोग ने महज़ धार्मिक आयोजन नहीं रहने दिया। लक्ष्य था– इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाना। इसके लिए प्रदेशभर के स्कूलों में प्रतियोगिताएँ हुईं, इतिहास से जुड़ी पुस्तकें बच्चों तक पहुँचीं और हजारों विद्यार्थियों को सम्मान पत्र दिए गए।

इसी क्रम में वीर बाल दिवस (प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में घोषित) पर निकाली गई वीर बाल रैली ऐतिहासिक बन गई– 8000 से अधिक स्कूली बच्चे , NCC, स्काउट-गाइड, खेल संघों की भागीदारी 7 1 किलोमीटर लंबी यात्रा जिसमे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहभागिता रही, तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर ऐतिहासिक चित्र प्रदर्शनी लगाईं गई। यह आयोजन एक समुदाय का नहीं, राष्ट्रीय वीरता की सामूहिक स्मृति का उत्सव था।

मुस्लिम समाजः पहचान नहीं, प्रेरणा

मुस्लिम समाज को लेकर आयोग का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट है। एपीजे अब्दुल

कलाम की जयंती पर ऐसे युवाओं को सम्मानित किया गया जो–नवाचार कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं ,सामाजिक उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। आयोग का कार्य केवल सुनवाई करना न होकर समाज में रचनात्मक कार्यो को लाना भी है।

छाबड़ा कहते हैं – 'अल्पसंख्यक में भी एक बड़ा वर्ग है। जो शासन की बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले जाता है जिससे एनी अल्पसंख्यक वर्ग के पास सरकारी योजनाएँ कम पहुँच पातीं है।'

मुस्लिम समाज की तरह जैन और सिख समाज को भी शासन की सभी योजनाये सीधे पहुंचे, रणनीति अपनाई जा रही है। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाये कमजोर वर्गों और महिला केन्द्रित होती है।

● प्रशासनिक सरलीकरण

आयोग जल्द ही एक समग्र वेबसाइट शुरू करने जा रहा है, जिसमें–केंद्र व राज्य सरकार की सभी लाभकारी योजनाएँ ,पात्रता,आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, शिकायत निवारण की जानकारी आदि एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। उद्देश्य है–जानकारी के अभाव में कोई वंचित न रहे।

● जिला कल्याण समितियाँ और 20 सूत्री कार्यक्रम

पूर्व में संचालित सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण समितियों को भंग कर अब–ज़िला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति गठन और 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया जायेगा, ताकि योजनाएँ काग़ज़ से निकलकर ज़मीन पर उतरें।

● हलाल-झटका विवाद

खान-पान को लेकर लंबे समय से चले आ रहे हलाल और झटका विवाद पर आयोग के पास शिकायते आ रही थी जिस पर आयोग ने व्यावहारिक समाधान सुझाया है–

'हमारी मांग है कि होटल और रेस्टोरेंट साफ़-साफ़ लिखें कि क्या परोसा जा रहा है–बोर्ड पर भी और मेन्यू में भी।'

यह धार्मिक टकराव नहीं, बल्कि उपभोक्ता की जानकारी का अधिकार है।

● हॉस्टल, शिक्षा और समान अवसर

50 कमरों वाला अल्पसंख्यक हॉस्टल वर्षों से बंद पड़ा था वर्तमान में प्रयास के बच्चे यहाँ पर रह रहे है । इसपर आयोग ने पहल करते हुए शासन को पत्र लिखा है। हमारा प्रयास है कि इस सत्र से इसे हम शुरु कर सके। पदभार ग्रहण के दिन ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा की उपस्थिति में उसका उद्घाटन हुआ।यह हॉस्टल पाँचों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए

बराबर अनुपात के आधार पर पूरी तरह सरकारी व्यवस्था के साथ संचालित होगा। आने वाले समय में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल की भी योजना है।

● अल्पसंख्यक का अर्थ: विशेष नहीं, समान

संवाद के अंत में छाबड़ा कहते हैं– 'अल्पसंख्यक की परिभाषा ही 'अल्प' है। समान अवसर देना भेदभाव नहीं होता। अगर किसी वर्ग की सीट खाली रहती है तो उसे दूसरों को दिया जा सकता है। यही समानता है।'

अमरजीत सिंह छाबड़ा का कार्यकाल किसी नारे की तरह नहीं, एक संकेत की तरह पढ़ा जाना चाहिए। यह संकेत उस दौर में आया है जब पहचान की राजनीति राष्ट्र की आत्मा पर हावी होने की कोशिश कर रही है। छाबड़ा का संदेश साफ़ है–धर्म व्यक्ति की पहचान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र उसकी चेतना है। और जब चेतना कमजोर होती है, तब पहचानें टकराने लगती हैं।

अल्पसंख्यक आयोग अगर इसी संतुलन के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी भूमिका शिकायत-निवारण तक सीमित नहीं रहेगी। वह केवल अधिकारों की सूची नहीं बनेगा, बल्कि जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला मंच बनेगा। क्योंकि अधिकार जब कर्तव्य से कट जाते हैं, तो वे संवाद नहीं, टकराव पैदा करते हैं।

आज देश को ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की ज़रूरत है जो वर्गों के बीच दीवार न खड़ी करें, बल्कि पुल बनें। आयोग अगर संरक्षण के साथ समावेशन की भाषा बोले, तुष्टिकरण के बजाय भरोसे की राजनीति करे, और अलगाव नहीं, साझेदारी का भाव पैदा करे– तो वह अल्पसंख्यकों का नहीं, राष्ट्र का आयोग कहलाएगा।

अमरजीत सिंह छाबड़ा का कार्यकाल यही उम्मीद जगाता है कि अल्पसंख्यक अधिकार राष्ट्र-विरोध नहीं होते, वे राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के लिए होते हैं। और शायद यही वह बिंदु है जहाँ संविधान काग़ज़ से निकलकर चेतना बनता है–और संस्थाएँ महज़ कार्यालय नहीं, राष्ट्रीय समरसता की प्रयोगशालाएँ बन जाती हैं।

सम्मानजनक रोज़गार की राह- 'हुनर का लंगर'

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, छ.ग. शासन

छाबड़ा स्पष्ट कहते हैं— 'हर बच्चा अफ़सर बने, यह आवश्यक नहीं मगर हुनरमन्द होना भी जरुरी है।' बच्चों को यह सिखाना भी जरुरी है कोई काम छोटा नहीं होता? 'हुनर का लंगर' इसी मानसिकता को बदलने की कोशिश है। लंगर—जो परंपरागत रूप से भोजन का प्रतीक रहा है—यहाँ कौशल और सम्मान का रूप लेता है। पहल के तहत गुरुद्वारों से अपील की गई है कि वे अपने परिसरों में कम से कम दो कमरे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए आरक्षित करें। समाज को अच्छे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारीगर भी चाहिए।

यह धार्मिक स्थानों को केवल आस्था तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण का केंद्र बनाता है।'हुनरमन्द' नामक इस पहल में फुलकारी, पटियाला सूट, घरेलू उत्पाद, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक कौशलों को आधुनिक बाज़ार से जोड़ने की योजना है। यह केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि रोज़गार की पूरी श्रृंखला तैयार करने का प्रयास है— जहाँ हुनर सीखने वाला व्यक्ति सिर्फ़ आत्मनिर्भर नहीं बनता, बल्कि दूसरों को भी रोज़गार देने की स्थिति में आता है।

छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की नई पहचान

डॉ. अभिमन्यु साहू
आयुर्वेद विशेषज्ञ, रायपुर

भागदौड़ भरी ज़िंदगी, अनियमित खानपान और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव। आज का इंसान इन्हीं तीन कारणों से सबसे अधिक बीमार हो रहा है। डायबिटीस , ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग और पाचन संबंधी समस्याएँ अब उम्र नहीं देखतीं। ऐसे समय में आयुर्वेद एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यह इलाज नहीं, जीवनशैली सुधारने की चिकित्सा पद्धति है।

आयुर्वेदः इलाज से आगे की सोच

आयुर्वेद भारत की लगभग पाँच हज़ार वर्ष पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। इसका मूल सिद्धांत है—शरीर, मन और प्रकृति के बीच संतुलन। आयुर्वेद मानता है कि शरीर में वात, पित्त और कफ—ये तीन दोष जब संतुलन में रहते हैं, तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब इनमें असंतुलन होता है, तब बीमारी जन्म लेती है।

आधुनिक चिकित्सा जहाँ अधिकतर रोग के लक्षणों पर काम करती है, वहीं आयुर्वेद बीमारी की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आज जब लोग बार-बार दवाइयाँ खाने के बावजूद पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते, तो उनका झुकाव आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है।

> “
>
> आयुर्वेद इन समस्याओं को केवल दवा से नहीं, बल्कि दिनचर्या, आहार और मानसिक संतुलन के ज़रिए सुधारता है। पंचकर्म जैसी शोधन प्रक्रियाएँ शरीर को अंदर से साफ़ करती हैं, वहीं जड़ी-बूटियाँ शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।

जीवनशैली रोगों में आयुर्वेद की भूमिका

आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ हैं। देर रात तक जागना, मोबाइल और स्क्रीन का अधिक उपयोग, असंतुलित भोजन और शारीरिक श्रम की कमी—इन सबका असर सीधे शरीर पर पड़ता है। आयुर्वेद इन समस्याओं को केवल दवा से नहीं, बल्कि दिनचर्या, आहार और मानसिक संतुलन के ज़रिए सुधारता है। पंचकर्म जैसी शोधन प्रक्रियाएँ शरीर को अंदर से साफ़ करती हैं, वहीं जड़ी-बूटियाँ शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।

छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की स्थिति

छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदः संभावनाएँ और चुनौतियाँ

छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसके व्यापक विकास के मार्ग में अभी भी कई व्यावहारिक बाधाएँ मौजूद हैं। परंपरा और जनविश्वास होने के बावजूद आयुर्वेद को वह संरचनात्मक समर्थन नहीं मिल पाया है, जिसकी आज आवश्यकता है।

पहली चुनौती - जागरूकता की कमी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेद के वैज्ञानिक लाभों और उपचार पद्धतियों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। आयुर्वेद को अक्सर घरेलू नुस्खों तक सीमित समझ लिया जाता है, जबकि गंभीर और दीर्घकालिक रोगों के लिए लोग केवल आधुनिक चिकित्सा पर निर्भर रहते हैं।

दूसरी चुनौती - अधोसंरचना और सुविधाओं का अभाव

कई क्षेत्रों में आधुनिक उपकरणों, डायग्नोस्टिक सुविधाओं और विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की उपलब्धता सीमित है। मल्टीस्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की कमी के कारण मरीजों को संपूर्ण उपचार एक ही स्थान पर नहीं मिल पाता।

तीसरी चुनौती - सरकारी योजनाओं में सीमित कवरेज

आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में अभी भी आयुर्वेदिक उपचारों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो आर्थिक कारणों से

आयुर्वेदिक इलाज नहीं करा पाते।

चौथी चुनौती - आधुनिक चिकित्सा का वर्चस्व

तुरंत राहत की चाह में लोग केमिकल-बेस्ड दवाओं और आधुनिक उपचारों को प्राथमिकता देते हैं। आयुर्वेद, जो धीरे लेकिन जड़ से असर करता है, अक्सर इस जल्दबाज़ी में पीछे छूट जाता है।

पाँचवीं चुनौती - प्रशिक्षित विशेषज्ञों और शोध की कमी

हर क्षेत्र में कुशल और अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है। साथ ही, वैज्ञानिक शोध और प्रमाणिक अध्ययन की कमी के कारण कई बार लोगों का भरोसा पूरी तरह नहीं बन पाता।

इन सभी कारणों से छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद अभी अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित नहीं हो पाया है, हालांकि यह भी सच है कि बीते कुछ वर्षों में लोगों की Awareness और Acceptance लगातार बढ़ रही है।

चुनौतियों का समाधान

इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम ज़रूरी हैं—

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद हेल्थ कैंप, कार्यशालाएँ और जन-जागरूकता कार्यक्रम।
- आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं से लैस, स्वच्छ और व्यवस्थित आयुर्वेदिक अस्पताल।
- आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में आयुर्वेदिक उपचारों को शामिल करना।
- वैज्ञानिक वैलिडेशन, रिसर्च सेंटर और एडवांस आयुर्वेदिक कोर्स को बढ़ावा देना।

आधुनिक दौर में आयुर्वेद का बदला स्वरूप

आज आयुर्वेद केवल वैद्य तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीक, वैज्ञानिक शोध और नई थेरेपी शामिल हो चुकी हैं। इम्युनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग और प्राकृतिक स्किन केयर—ये सभी आयुर्वेद के आधुनिक रूप हैं। कोविड महामारी के बाद लोगों ने यह महसूस किया कि केवल इलाज नहीं, बल्कि मजबूत रोग-प्रतिरोधक क्षमता ही असली सुरक्षा है। इस सोच ने आयुर्वेद को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है।

आयुर्वेद क्यों अपनाएँ

आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शरीर के साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करता। इलाज धीरे-धीरे, लेकिन जड़ से असर करता है। प्राकृतिक औषधियाँ होने के कारण इसके दुष्प्रभाव भी न्यूनतम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद व्यक्ति को अपने शरीर को समझने और उसके अनुसार जीने की कला सिखाता है।

आज आवश्यकता है कि हम बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर स्वास्थ्य को अपनी आदत बनाएँ। आयुर्वेद इसी सोच को मजबूत करता है। क्योंकि आयुर्वेद केवल एक इलाज नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की सोच है। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद के विस्तार की संभावनाएँ बहुत बड़ी हैं। ज़रूरत है जागरूकता, आधुनिक सुविधाओं और विश्वास की।

डॉ. अभिमन्यु आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है, जहाँ परंपरा और आधुनिक चिकित्सा एक साथ चलती हैं। यदि समय रहते आयुर्वेद को अपनाया जाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल इलाज नहीं, स्वस्थ जीवन की विरासत पाएँगी।

भरोसे की पहल

DR. ABHIMANYU'S
AYURVEDA MULTISPECIALITY HOSPITAL
PAIN | PANCHKARMA | PILES | PEDIA | GYNAE | SKIN

रायपुर स्थित डॉ. अभिमन्यु आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह राज्य का पहला ऐसा आयुर्वेदिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है, जहाँ पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक जांच सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। यहाँ इलाज केवल रोग पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरी जीवनशैली पर केंद्रित होता है। हर मरीज के लिए अलग उपचार योजना बनाई जाती है, जिसमें उसकी उम्र, दिनचर्या, भोजन और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

अस्पताल में विशेष रूप से जोड़ों के दर्द, गठिया, पीठ दर्द और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। इसके अलावा पेट की गड़बड़ियाँ, त्वचा रोग, बालों की समस्याएँ, महिलाओं से जुड़ी परेशानियाँ और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पंचकर्म, हर्बल उपचार और जीवनशैली परामर्श के ज़रिए मरीजों को दीर्घकालिक लाभ मिल रहा है। कई मरीज ऐसे हैं, जो लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर रहने के बाद आयुर्वेद से संतुलित जीवन की ओर लौटे हैं।

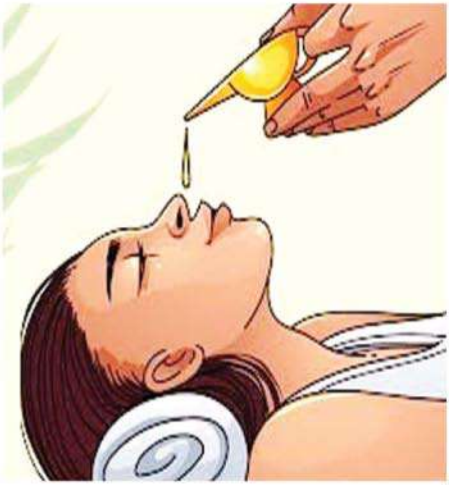

‘धड़कन’ ने ज़िंदगी की दिशा बदल दी

‘आपके बच्चे की धड़कन बाकी बच्चों से तेज़ है’, गांव की मितानिन के ये शब्द आज भी रजनी यादव के कानों में गूंजते हैं। बात करते-करते उनकी आंखें भर आती हैं— ‘हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आज लगता है, काश उस दिन रुक गए होते।’

रायपुर जिले के गोगांव की रहने वाली रजनी यादव का तीसरा बेटा अरमान, अपने दोनों बड़े भाइयों और दोस्तों के साथ बिल्कुल सामान्य बचपन जी रहा था। कभी पिट्ठूल, कभी दौड़, कभी स्कूल की शरारतें—सब कुछ वैसा ही, जैसा किसी भी गांव के बच्चे का होता है।

बस एक बात थी जो बार-बार परेशान करती थी—सर्दी और बुखार। माता-पिता ने इसे आम बीमारी समझा, किसी अनहोनी की कल्पना तक नहीं की। उन्हें क्या पता था कि उस मासूम हंसी के पीछे एक खामोश खतरा छिपा बैठा है।

एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया

13 दिसंबर 2025 को सरोरा स्थित शासकीय स्कूल में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर चिरायु टीम बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कर रही थी। जब अरमान की बारी आई, डॉक्टर एक पल के लिए ठिठक गए। स्टेथोस्कोप हटाकर उन्होंने दोबारा सुना। दिल की धड़कन सामान्य नहीं थी। यही वह क्षण था, जिसने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी की दिशा बदल दी।

समय पर पकड़ी गई बीमारी -प्रोजेक्ट 'धड़कन'

छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य पहल प्रोजेक्ट ‘धड़कन’ का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease – CHD) की समय रहते पहचान और निःशुल्क इलाज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर रायपुर जिले में इसे जिला प्रशासन, चिरायु टीम और श्री सत्य साई नारायण हॉस्पिटल, नया रायपुर के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

अरमान को तुरंत नया रायपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया। विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट आई— दिल में 18 मिमी का छेद। डॉक्टरों ने बिना किसी देरी के साफ कहा— ‘ऑपरेशन ज़रूरी है, और जल्द।’

गरीबी बनाम बीमारी और भरोसे की जीत

ईंट-भट्ठे में काम करने वाले पिता रंगनाथ यादव और मां रजनी के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा था—पैसे कहां से आएंगे? बच्चा बचेगा या नहीं? भविष्य कैसा होगा? लेकिन उस कठिन घड़ी में उन्होंने हार नहीं मानी। चिरायु टीम की सलाह पर भरोसा किया। 28 दिसंबर 2025, प्रोजेक्ट ‘धड़कन’ के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में अरमान का जटिल हृदय ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क सफलतापूर्वक किया गया। कुछ दिनों की निगरानी और देखभाल के बाद अरमान घर लौट आया—एक नई ज़िंदगी लेकर।

आज की धड़कन बनी कल की उम्मीद

आज जब अरमान फिर से पिट्ठूल खेलता है, दोस्तों के पीछे दौड़ता है, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि कुछ ही दिन पहले वह ऑपरेशन थिएटर में था। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी सेहत में लगातार सुधार है और वह पूरी तरह स्वस्थ है। चिरायु टीम का नियमित फॉलो-अप जारी है। भावुक होकर रजनी यादव कहती हैं—

‘अगर समय पर जांच और इलाज नहीं मिलता, तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे सामने न होता।’

पिता रंगनाथ यादव की आवाज़ भर आती है— ‘मेरे पास न पैसा था, न साधनञ् लेकिन प्रोजेक्ट धड़कन ने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दे दी।’

कहानी नहीं, एक मिसाल है

यह कहानी सिर्फ अरमान के बचने की नहीं है। यह कहानी है संवेदनशील शासन, समय पर हस्तक्षेप और उस भरोसे की—जो एक मासूम दिल को दोबारा धड़कने का मौका दे सका। आज अरमान केवल अपने माता-पिता का सहारा नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए आशा, विश्वास और समय पर मिली मदद की ताकत का प्रतीक बन चुका है। रजनी और रंगनाथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन और चिरायु टीम के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थकते।

कभी-कभी एक सही समय पर सुनी गई धड़कन, पूरी ज़िंदगी बचा लेती है।

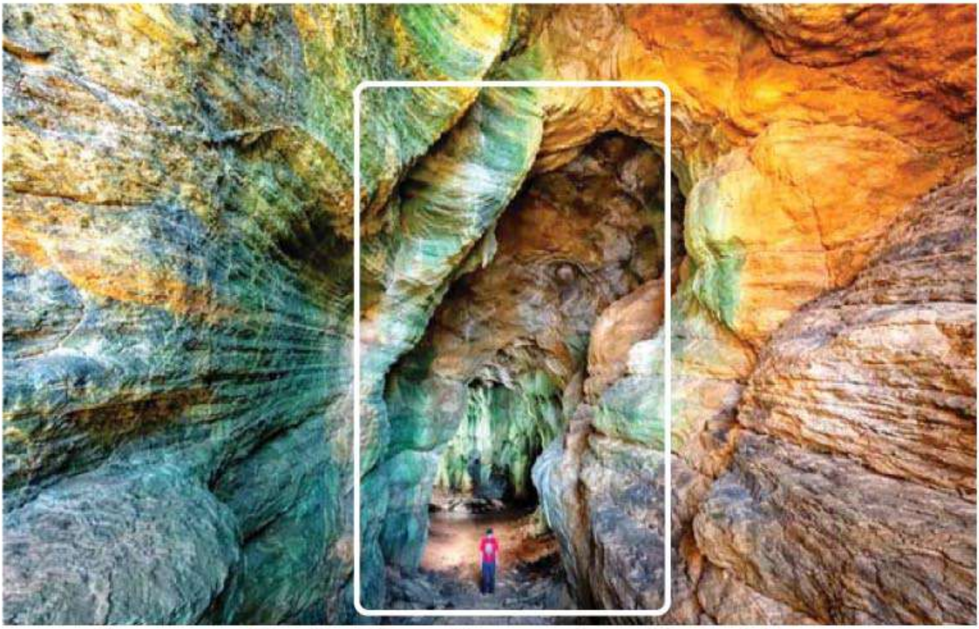

कांगेर घाटी में मिली अनोखी 'ग्रीन गुफा'

छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश में विख्यात है। इसी कड़ी में अब कांगेर घाटी में एक और अनोखी प्राकृतिक स्थलाकृति सामने आई है, जिसे 'ग्रीन केव' (ग्रीन गुफा) नाम दिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और वन्य धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रीन गुफा के पर्यटन मानचित्र में शामिल होने से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति प्राप्त होगी और शीघ्र ही पर्यटक इस अद्भुत गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। वन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण किए जाने के बाद शीघ्र ही इस गुफा को पर्यटकों के लिए खोले जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि यह ग्रीन गुफा कोटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों और छत से लटकती चूने की आकृतियों (स्टैलेक्टाइट्स) पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे 'ग्रीन केव' नाम दिया गया है। चूना पत्थर और शैल से निर्मित यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ और विशिष्ट गुफाओं में से एक मानी जा रही है।

ग्रीन गुफा तक पहुंचने का मार्ग बड़े-बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है। गुफा में प्रवेश करते ही सूक्ष्मजीवी जमाव से ढकी हरी दीवारें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जहां से भीतर की ओर चमकदार और विशाल स्टैलेक्टाइट्स तथा फ्लो-स्टोन (बहते पानी से बनी पत्थर की परतें) देखने को मिलती हैं, जो गुफा की प्राकृतिक भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं।

> घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है।

घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहुंच मार्ग, पैदल पथ तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। वन विभाग द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

गिद्ध संरक्षण में छत्तीसगढ़ की नई उड़ान

इंद्रावती टाइगर रिजर्व बना देश का मॉडल

धनंजय राठौर

संयुक्त संचालक जनसम्पर्क

छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में देशभर के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य भारत के सबसे स्वच्छ नदी–वन पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल यह रिजर्व अब केवल बाघों और जंगली भैंसों का ही नहीं, बल्कि विलुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

गिद्ध पर्यावरण के 'सफाईकर्मी'

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार इंद्रावती के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गिद्धों सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण कर इनकी घटती आबादी को बचाना और बढ़ाना है, क्योंकि गिद्ध पर्यावरण के 'सफाईकर्मी' हैं और इनके बिना बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गिद्धों के अस्तित्व पर जहरीली दवाओं, असुरक्षित शव निपटान और मानव हस्तक्षेप जैसे गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में उपग्रह (सैटेलाइट) टेलीमेट्री आधारित निगरानी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

गिद्ध लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं सक्रिय

छत्तीसगढ़ में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें उच्च-रिज़ॉल्यूशन गिद्ध गतिविधि डेटा का उपयोग संरक्षण कार्यों की दिशा तय करने के लिए किया जा रहा है। अब तक के आंकड़ों से पता चला है कि गिद्ध लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और घने जंगलों व मानव बस्तियों के बीच लगातार आवाजाही करते हैं।

वन्यजीव प्रबंधन को मिली नई वैज्ञानिक दिशा

गौरतलब है कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। राज्य में पहली बार दो गिद्धों की सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से 18,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले GPS डेटा पॉइंट्स प्राप्त किए गए हैं, जिससे वन्यजीव प्रबंधन को नई वैज्ञानिक दिशा मिली है। इस सफलता में क्षेत्रीय जीवविज्ञानी श्री सूरज कुमार के नेतृत्व में 'गिद्ध मित्र दल' (गिद्ध संरक्षण स्वयंसेवक दल) की अहम भूमिका रही है। यह दल घोंसलों की निगरानी, शवों के सुरक्षित प्रबंधन और स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी सामुदायिक सहयोग का परिणाम है कि 'गुड्डा सारी गुट्टा' जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पहली बार निर्बाध प्रजनन सुनिश्चित हो सका है।

वुल्चर रेस्टोरेंट की स्थापना

संरक्षण प्रयासों के तहत उप-निदेशक श्री संदीप बलागा के पर्यवेक्षण में 'वुल्चर रेस्टोरेंट' की स्थापना भी की गई है। यह नियंत्रित भोजन स्थल हैं, जहां केवल पशु चिकित्सा परीक्षण के बाद NSAID–मुक्त शव ही रखे जाते हैं। इससे गिद्धों को सुरक्षित भोजन मिल रहा है। साथ ही ये केंद्र सामुदायिक शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जहां स्कूलों और स्थानीय युवाओं को पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है।

गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (Vulture Safe Zone) की स्थापना

भविष्य की रणनीति के तहत कार्यक्रम के तीसरे चरण का नेतृत्व भी उप-निदेशक श्री संदीप बलागा करेंगे। इस चरण में तीन अतिरिक्त गिद्धों की सैटेलाइट टैगिंग, 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, पंचायतों की भागीदारी से 100 किलोमीटर क्षेत्र में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (Vulture Safe Zone) की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ की पहली गिद्ध पुनर्वास कार्ययोजना के प्रकाशन का लक्ष्य रखा गया है। तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता को एक सूत्र में पिरोते हुए इंद्रावती टाइगर रिजर्व यह संदेश दे रहा है कि दूरदर्शी नेतृत्व में जंगल और लोग साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

पानी में ज़हर, फाइलों में धूलः भागीरथपुरा की प्रशासनिक हत्या

इंदौर के भागीरथपुरा में 16 लोगों की जान गई—लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मौतें हादसा थीं या फिर तीन साल की लापरवाही का नतीजा? दूषित पानी की शिकायतें थीं, फाइलें थीं, टेंडर थे, मंज़ूरियाँ थीं—सब कुछ था। नहीं थी तो सिर्फ़ संवेदनशीलता और जवाबदेही। यह खबर किसी एक पाइपलाइन की नहीं है, यह खबर उस सिस्टम की है जो मौत के बाद ही जागता है। पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव तीन साल तक मेजों पर धूल खाता रहा और लोग ज़हर पीते रहे।

जी बात उसी भागीरथपुरा की हो रही है ,जहाँ फाइलें ज़िंदा रहीं और लोग मरते चले गए। जहाँ मौत ने वह काम 24 घंटे में करा दिया, जो सिस्टम आठ महीने में नहीं कर पाया। भागीरथपुरा की गलियों में जो मरा, वह सिर्फ़ पानी नहीं था। वहाँ भरोसा मरा। वहाँ व्यवस्था मरी। वहाँ वह सिस्टम मरा, जो हर बार लाशों के बाद ही जागता है। इंदौर के भागीरथपुरा में 16 लोगों की मौत किसी 'अचानक हुई दुर्घटना' का नतीजा नहीं थी। यह एक तीन साल लंबी प्रशासनिक हत्या थी—जिसमें फाइलें हथियार थीं, और देरी सबसे बड़ा अपराध।

■ **कहानी की शुरुआत-** जब सबको पता था, फिर भी सब चुप थे। भागीरथपुरा में दूषित पानी कोई नई समस्या नहीं थी। शिकायतें लगातार मिल रही थीं। लोग बदबूदार, गंदा पानी पीने को मजबूर थे। हालात की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने जुलाई 2022 में पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया शुरू करवाई। ?2.40 करोड़ का टेंडर जारी हुआ। 23 नवंबर 2022 को फाइल जलकार्य समिति को भेजी गई। 25 नवंबर 2022 को महापौर परिषद ने प्रस्ताव को मंज़ूरी भी दे दी। यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद सिस्टम ने अपना असली चेहरा दिखाया। तीन महीने, सिर्फ़ हस्ताक्षरों के लिए ,जिस फाइल का संबंध सीधे लोगों की सेहत और जीवन से था, वह महीनों तक मेजों पर भटकती रही। 3 फरवरी 2023—ढाई महीने बाद अपर आयुक्त के हस्ताक्षर। 6 फरवरी 2023—महापौर पुष्यमित्र भार्गव के हस्ताक्षर। सवाल सीधा है— क्या इंसानी जानों की कीमत सिर्फ़ दो साइन थी? अगर हाँ, तो तीन महीने क्यों लगे? वर्क ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन कामज? काम आज भी अधूरा है। साढ़े तीन साल बीत गए, पाइपलाइन पूरी नहीं हुई।

बहाने और हकीकत

जब सवाल उठे तो महापौर की सफाई आई— 'टेंडर में सिर्फ़ एक ठेकेदार था, मालवा इंजीनियर। उसका पिछला काम संतोषजनक नहीं था।' लेकिन सवाल यह नहीं कि टेंडर एक था या दो। सवाल यह है कि जब लोगों को ज़हर मिल रहा था, तब सिस्टम टेस्टिंग मोड में क्यों था? दूसरा चरण-मौत के इंतज़ार में बैठा सिस्टम। दूसरे चरण की फाइल 12 नवंबर 2024 को ही तैयार हो गई थी। लेकिन टेंडर जारी हुआ—8 अगस्त 2025 को। यानी पूरे 9 महीने बाद।

17 सितंबर 2025 को टेंडर खोलने की तारीख थी, लेकिन न टेंडर खुले, न काम शुरू हुआ। रू.2.40 करोड़ की फाइल अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया की मेज पर धूल खाती रही। इसी दौरान भागीरथपुरा में नालियों का गंदा पानी पीने की लाइन में मिलता रहा। लोग शिकायत करते रहे। उनकी आवाज़ दफ्तरों की मोटी दीवारों से टकराकर लौटती रही। फिर वही हुआ, जिसका डर था। मौत ने वह कर दिया, जो फाइलें नहीं कर सकीं तीन दिनों में 16 मौतें। सैकड़ों बीमार। शहर में हड़कंप। और देखिए सिस्टम की रफ्तार— 30 दिसंबर 2025 को वही फाइल, जो 8 महीने से पड़ी थी, एक दिन में साइन हो गई। अगले दिन टेंडर खुला। वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी। यानि साफ़ है— फाइलें इंसानी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थीं, लेकिन इंसानी मौत फाइल से ज़्यादा ताकतवर निकली।

निलंबन, लेकिन क्या यही न्याय है?

सरकार ने कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव हटाए गए। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया और कार्यपालन अभियंता संजय श्रीवास्तव निलंबित। लेकिन फाइलों की नोटशीट गवाही देती है— यह सिर्फ़ अफसरों की लापरवाही नहीं थी। नेता भी उतने ही दोषी हैं। पाइपलाइन 27 साल पुरानी थी, लेकिन मौत नई है। निलंबित इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव का बयान अहम है— 1998 में डली पाइपलाइन सामान्यत: 30-35 साल चल सकती थी। समस्या तब शुरू हुई जब बार-बार खुदाई में पाइप लाइन छेदती गई। ड्रेन का पानी पीने की लाइन में मिलने लगा। यानी मौत अचानक नहीं आई— उसे सालों तक बुलाया गया।

राजनीति का असंवेदनशील चेहरा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक लेकर कहा— 'ऐसी स्थिति फिर न बने।' लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सब कुछ कह गया—जब रिपोर्टर ने इलाज के खर्च पर सवाल किया, तो जवाब मिला—'कट सवाल मत पूछो।' यही संवेदना है? कोर्ट, विपक्ष और सवाल जो बाकी हैं हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिकाएँ दाख़लि हुईं। कोर्ट ने साफ़ कहा—इलाज मुफ्त देना ही पड़ेगा। 2 जनवरी को पूरी रिपोर्ट तलब की गई।कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री से इस्तीफ़े की मांग की।

अंत में सवाल सिर्फ़ एक

भागीरथपुरा में जो हुआ, वह हादसा नहीं था। वह व्यवस्था का चरित्र प्रमाणपत्र था। जब तक फाइलें लाशों से तेज़ नहीं चलेंगी, जब तक जवाबदेही सिर्फ़ निलंबन तक सीमित रहेगी, तब तक हर शहर में एक नया भागीरथपुरा तैयार होता रहेगा। और फिर कोई पूछेगा-'मौत के बाद सिस्टम इतना फुर्तीला क्यों हो जाता है?'

प्रदूषण फैलाते छत्तीसगढ़ के मेडिकल हब

अस्पतालों को हम जीवन का आख़िरी भरोसा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है—अगर वही अस्पताल हवा, पानी और ज़मीन को ज़हर बना रहे हों तो इलाज किसका हो रहा है और बीमारी किसकी फैल रही है? आज प्रदेश के कई हिस्सों में अस्पताल बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को केवल फाइलों तक सीमित रखे हुए हैं। इस्तेमाल की गई सिरिंज, खून से सने पट्टे, दवाइयों की एक्सपायरी बोतलें—सब कुछ एक ही कचरे में। नतीजा यह कि संक्रमण अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज में फैल रहा है। यह सिर्फ़ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, यह संरचनात्मक अनैतिकता है। जिस डॉक्टर की शपथ 'जीवन बचाने' की होती है, उसी व्यवस्था के भीतर पर्यावरण को मारने का मौन अपराध चल रहा है।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को विकास का संकेत माना जाता है। नए अस्पताल, नए मेडिकल कॉलेज, नई मशीनें—सब कुछ आधुनिकता की भाषा बोलता है। लेकिन इस विस्तार के साथ-साथ पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी सिकुड़ती चली गई। चमकदार इमारतों की छाया में एक कड़वी सच्चाई दबी हुई है—इलाज के नाम पर पर्यावरण को ज़हर बनाया जा रहा है। यह कोई भावनात्मक आरोप नहीं। यह निष्कर्ष RTI से प्राप्त दस्तावेज़ों, सरकारी आंकड़ों और ज़मीनी हालात से निकलता है। छत्तीसगढ़ के शहरी केंद्र—रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा—आज राज्य के मेडिकल हब बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है— इन अस्पतालों से रोज़ निकलने वाले बायो-मेडिकल कचरे का वैज्ञानिक निपटान कौन कर रहा है?

छत्तीसगढ़ पहले ही औद्योगिक प्रदूषण और कोयला आधारित परियोजनाओं का बोझ झेल रहा है।ऐसे में अस्पतालों से निकलने वाला जहरीला कचरा इस बोझ को और भारी कर रहा है।फर्क बस इतना है—फैक्ट्रियों से निकलता धुआँ दिखता है, लेकिन अस्पतालों से निकलता ज़हर अदृश्य होता है। और जो प्रदूषण दिखता नहीं, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।

RTI के जवाब बताते हैं—

- **कई अस्पतालों के पास वैध बायो-मेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन नहीं है . न ही वर्षों से वार्षिक रिपोर्ट जमा की और कुछ तो बिना नवीनीकरण के ही संचालित**

यानी नियम मौजूद हैं, लेकिन पालन इच्छा पर निर्भर है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार— प्रतिदिन टन के हिसाब से बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पन्न हो रहा है मगर CBWTF (कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी) या तो कम हैं,या पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहीं . नतीजा—

कचरा सामान्य कचरे में , खुले में या अवैध रूप से जलाया/दफनाया जा रहा है और यह सिर्फ़ पर्यावरण ही नहीं, जनस्वास्थ्य को भी संक्रमित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए यह अपराध इसलिए भी गंभीर है क्योंकि—

- राज्य पहले से औद्योगिक प्रदूषण झेल रहा है
- कई इलाके भूजल पर पूरी तरह निर्भर हैं
- स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच समान नहीं

ऐसे में अस्पतालों की लापरवाही दो पीढ़ियों को प्रभावित करती है। यह प्रदूषण केवल हवा में नहीं, बल्कि नालियों, ज़मीन और पानी के रास्ते गाँवों तक फैलता है। जब अस्पताल खुद को 'सेवा' की जगह 'उद्योग' मानने लगते हैं, तब पर्यावरण पहला शिकार बनता है। अब समय आ गया है कि—

- अस्पतालों को भी उद्योगों की तरह पर्यावरणीय ऑडिट के दायरे में लाया जाए
- नागरिक समाज इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े
- प्रशासन 'स्वास्थ्य सेवा' के नाम पर चल रहे इस प्रदूषण को अपराध की तरह देखे

क्योंकि- जो इलाज के नाम पर ज़हर फैलाए, वह अस्पताल नहीं—सिस्टम की बीमारी है।

शासन-प्रशासन की चुप्पी : समस्या की गहरी जड़

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नियम बनाने वाला और पालन करवाने वाला शासन-प्रशासन अक्सर पीछे हटता है— राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग—तीनों के बीच जिम्मेदारी बंटी हुई है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। निरीक्षण अक्सर सूचना देकर होते हैं, जुर्माने नाममात्र के होते हैं,और रिपोर्टें फाइलों में दफन हो जाती हैं। विडंबना यह है कि जिन अस्पतालों के पास प्रभाव, विज्ञापन बजट और राजनीतिक पहुँच है— वही नियमों को सबसे अधिक तोड़ते पाए जाते हैं। छोटे नर्सिंग होम पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े संस्थान 'प्रबंधन सुधार' के नाम पर बच निकलते हैं। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, संस्थागत संरक्षण का मामला है।

बड़े अस्पताल जिनके पास राजनीतिक पहुँच, विज्ञापन बजट और प्रभाव है, वे नियम तोड़ते हैं। छोटे नर्सिंग होम पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े संस्थान 'प्रबंधन सुधार' के बहाने बच निकलते हैं। यानी केवल अस्पताल की लापरवाही नहीं, शासन-प्रशासन की उदासीनता भी समस्या की जड़ है। सिस्टम जानता है, देखता है— लेकिन टकराने से बचता है।

छत्तीसगढ़ को 'हेल्थ मॉडल स्टेट' बनाना है, तो—

- सभी अस्पतालों का सार्वजनिक पर्यावरण अनुपालन डैशबोर्ड
- रीयल-टाइम BMW ट्रैकिंग सिस्टम
- नियम तोड़ने वाले अस्पतालों के नाम सार्वजनिक करना
- CBWTF की संख्या और क्षमता का जिला-स्तरीय विस्तार
- 'स्वास्थ्य सेवा' की आड़ में प्रदूषण को दंडनीय अपराध मानना

और प्रशासन को अब काग़ज़ी औपचारिकताओं से बाहर निकलकर, सखूत कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। छत्तीसगढ़ को अगर भविष्य सुरक्षित करना है, तो इलाज सिर्फ़ मरीज़ों का नहीं—अस्पतालों की व्यवस्था, मानसिकता और प्रशासनिक रवैये का भी करना होगा। क्योंकि जो आज उपचार के नाम पर ज़हर फैलाता है, वह कल पूरे राज्य की स्वास्थ्य विरासत को खतरे में डाल देगा।

जांच की श्रंखला जारी है .....

स्वच्छता, संवाद और संगठन

रायपुर उत्तर विधानसभा में जनसेवा के तीन आयाम

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीते दिनों जनसेवा, स्वच्छता अभियान और संगठनात्मक सक्रियता के तीन महत्वपूर्ण आयाम एक साथ देखने को मिले। विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्र में जहाँ एक ओर नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, वहीं दूसरी ओर आमजन से सीधे संवाद और संगठन को मजबूती देने की पहल भी प्रभावी रूप से सामने आई।

जगन्नाथ मंदिर परिसर में 10 सीटर सार्वजनिक शौचालय का भूमिपूजन

रायपुर स्थित पावन जगन्नाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 सीटर सार्वजनिक शौचालय निर्माण का विधिवत भूमिपूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा एवं रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे की गरिमामयी उपस्थिति रही।

यह पहल धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता, सुविधा और जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विधायक मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की आधारशिला है। धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकता है।

पार्षद कैलाश बेहरा की विशेष उपस्थिति

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम 'स्वच्छ रायपुर-सुंदर रायपुर' की संकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर जनहितकारी कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में पार्षदगण, नगर निगम के अभियंता, ठेकेदार, मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी आलोक सिंह, रघुमणि प्रधान सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जवाहर उद्यान में जनसुविधा विस्तार की पहल

इसी क्रम में सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 46 स्थित जवाहर उद्यान में भी सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया। यह उद्यान शहर का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहाँ प्रतिदिन वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और मॉर्निंग वॉक करने वालों की बड़ी संख्या में आवाजाही रहती है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महापौर मीनल चौबे ने भी नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन की भावना के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने का सशक्त उदाहरण है।

जनदर्शन में सुनी आमजन की पीड़ा

विधायक पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। विशेष रूप से शंकर नगर बी.टी.आई. ग्राउंड के पास सड़क किनारे सब्जी विक्रेताओं, गुमटी संचालकों और दिहाड़ी पर निर्भर लोगों ने अपनी समस्याएँ विधायक के समक्ष रखीं। मिश्रा ने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 'आमजन की समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता है और उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए मैं सदैव प्रतिबद्ध रहूँगा।' जनदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और सीधे संवाद के माध्यम से अपनी बात रखी।

संगठनात्मक मजबूती की दिशा में सौजन्य भेंट

भारतीय जनता पार्टी शंकर नगर मंडल की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने पार्षद कैलाश बेहरा की उपस्थिति में पावन जगन्नाथ मंदिर परिसर में विधायक पुरंदर मिश्रा से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर आत्मीय वातावरण में नव-नियुक्त पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएँ दी गईं। विधायक मिश्रा ने संगठनात्मक एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि 'संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और सेवा भाव पर निर्भर करती है।' उन्होंने प्रभु जगन्नाथ से सभी पदाधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

स्वच्छता अधोसंरचना का विस्तार, आमजन से सीधा संवाद और संगठनात्मक मजबूती–उत्तर रायपुर में हालिया गतिविधियाँ समग्र जनसेवा मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये पहलें न केवल नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि स्वच्छ, संवेदनशील और सहभागी शासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण संदेश देती हैं।

यात्री सुविधा से लेकर संरक्षा सुधार तक, भारतीय रेलवे की नई दिशा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा, संरक्षा और आधुनिक रेलवे प्रबंधन की दिशा में एक के बाद एक महत्वपूर्ण पहलें सामने आ रही हैं। जनवरी 2026 का यह दौर रायपुर रेल मंडल के लिए यात्री-केंद्रित नवाचार, संरक्षा संवर्धन और नीतिगत सुधारों का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है।

रायपुर स्टेशन पर पहली बार 'स्वस्थ वेटिंग लाउंज'

रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब ट्रेनों के इंतजार के दौरान स्वस्थ और आरामदायक अनुभव मिलने जा रहा है। भारतीय रेलवे की अभिनव NINFRIS (New Innovative Non-Fare Revenue Ideas Scheme) योजना के तहत पहली बार स्वस्थ वेटिंग लाउंज की सुविधा शुरू की गई है।

इस सुविधा का शुभारंभ रायपुर से बड़ोदरा जा रहे यात्री चंद्रकांत बलावंत तथा रायपुर से उज्जैन जा रहीं दो छात्राएं ओजस्वी एवं आरुषि द्वारा किया गया। यह पहल रेलवे की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें स्टेशन केवल यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुविधा और आराम का केंद्र बनते जा रहे हैं।

स्वस्थ वेटिंग लाउंज में यात्रियों को योगा एवं मेडिटेशन स्पेस, मिनी फिटनेस कॉर्नर, लाइट एक्सरसाइज इक्विपमेंट, आरामदायक सोफा एवं प्रीमियम रीक्लाइनर मसाज चेयर, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जिंग सुविधा, लाइव ट्रेन सूचना डिस्प्ले, फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग बाथरूम-टॉयलेट, तथा आवश्यकता पड़ने पर शुल्क आधारित एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही यात्रियों के लिए मिलेट्स आधारित हेल्दी फूड, वजन और बीपी जैसी सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। शांत वातावरण में योग और ध्यान के माध्यम से यात्री अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकेंगे। योग एवं ध्यान क्षेत्र तथा फिटनेस कॉर्नर के उपयोग हेतु रू.50 प्रति 30 मिनट शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी खाद्य सामग्री FSSAI मानकों के अनुरूप होगी।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के.पी. काशीपथी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक, मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश सिंह, सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नाममात्र शुल्क में प्रीमियम सुविधा

स्वस्थ वेटिंग लाउंज में प्रवेश हेतु

- 1 घंटे के लिए रु. 30
- 2 घंटे के लिए रु. 60
- 4 घंटे के लिए रु. 80

रेलवे में 52 बड़े सुधार-यात्री सुविधा और संरक्षा पर फोकस

दिनांक 08 जनवरी 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में रेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में रेलवे में 52 बड़े सुधार लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना एवं रवनीत सिंह बिट्टू, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में यह संकल्प लिया गया कि 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू कर कार्यकुशलता, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। विशेष रूप से रेल सुरक्षा पर जोर देते हुए बताया गया कि वर्ष 2014-15 में 135 कॉन्सिक्वेन्शियल रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 2025-26 में 11 रह गई है, जिसे अब सिंगल डिजिट तक लाने का लक्ष्य है।

इसके अलावा सुरक्षा, मेंटेनेंस और ऑपरेशन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं एडवांस टेक्नोलॉजी के उपयोग को तेज करने, कर्मचारियों के टैलेंट मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट, तथा फूड एवं कैटरिंग सेवाओं में बड़े सुधारों पर भी चर्चा की गई।

नई सोच, नया रेलवे

रायपुर रेल मंडल की ये पहलें स्पष्ट संकेत देती हैं कि भारतीय रेलवे अब केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि सुरक्षित, स्मार्ट और यात्री-केंद्रित सेवा तंत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्वस्थ वेटिंग लाउंज जैसी सुविधाएं, संरक्षा सुधार और तकनीकी नवाचार—ये सभी मिलकर नए भारत की नई रेलवे की तस्वीर गढ़ रहे हैं।

डोपामीन ड्रेसिंग और मॉडर्न ड्रेपिंगः 2026 का फैशन

अमृता कौर

इस साल भारतीय फैशन इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आई है—जहाँ रंगों की खुशी और ड्रेपिंग की सहूलियत एक साथ मिल रही हैं।

क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पसंद का ब्राइट पीला कुर्ता या वो इलेक्ट्रिक ब्लू साड़ी पहनी और अचानक आपका मूड एकदम से बदल गया? अगर हाँ, तो आप अनजाने में ही 'डोपामीन ड्रेसिंग' का हिस्सा बन चुकी हैं। डोपामीन हमारे मस्तिष्क का वह 'फील-गुड' केमिकल है जो हमें खुशी का अहसास कराता है। फैशन विशेषज्ञों का मानना है कि चमकीले रंग, बोल्ड प्रिंट्स और टेक्सचर हमारे मूड को बूस्ट करने की ताकत रखते हैं।

डोपामीन ड्रेसिंग-इस ट्रेंड को कैसे अपनाएं?

- **मोनोक्रोम मैजिक**- सिर से पैर तक एक ही ब्राइट रंग पहनें। यह आपको लंबा और प्रभावशाली दिखाता है।
- **एक्सेसरीज का तड़का**-अगर आप बहुत ब्राइट रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहतीं, तो एक न्यूट्रल ड्रेस के साथ %नियॉन हील्स% या 'हॉट पिंक बैग' कैरी करें।

जहाँ 2024 में 'क्वाइट लग्जरी' और बेज रंगों का चलन रहा, वहीं अब वर्ष 2026 में भारतीय महिलाएँ खुलकर जीवन जीने की प्रवृत्ति के अनुसार नियॉन पिंक, टैंगरीन ऑरेंज और कोबाल्ट ब्लू जैसे रंगों को पहनने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगी। बोल्ड कलर्स पहनने वाली महिलाओं में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होती है।

मॉडर्न ड्रेपिंग

साड़ी भारतीय महिला की पहचान है परंतु अब साड़ी सिर्फ शादी या पार्टी में पहनने के लिए नहीं बल्कि ऑफिस और कैजुअल लंच के लिए भी पहली पसंद बन गई है और इसे संभव बनाया है 'मॉडर्न ड्रेपिंग' ने। साड़ी पहनने में लगने वाला लंबा समय अब मॉडर्न ड्रेपिंग के जरिए कुछ ही मिनटों में बदल गया है और यह 'कंफर्ट' और 'कल्चर' का सही संगम है।

2026 के टॉप ड्रेपिंग स्टाइल

- **पॉकेट साड़ी**-फोन और चाबियाँ रखने के लिए साड़ी के भीतर छिपे हुए पॉकेट्स।
- **पैंट-स्टाइल ड्रेप**- लेगिंग्स या ट्राउजर के ऊपर साड़ी ड्रेप करना, जो भागदौड़ के लिए परफेक्ट है।
- **प्री-स्टिच्ड गाउन साड़ी**- जो दिखने में साड़ी है लेकिन पहनने में एक स्कर्ट की तरह आसान।

आज भारत में 60% से ज्यादा नए फैशन स्टार्टअप्स महिलाएँ चला रही हैं, ये उद्यमी केवल कपड़े नहीं बेच रहीं, बल्कि एक 'सस्टेनेबल लाइफस्टाइल' को बढ़ावा दे रही हैं। इको-फ्रेंडली कलर्स और स्थानीय कारीगरी को अपनाते हुए ये महिलाएँ 'वोकल फॉर लोकल' के द्वारा गाँव के बुनकरों को भी सीधे ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रही हैं।

फैशन अब किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को अच्छा महसूस करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए है। इसलिए अपनी अलमारी में एक ऐसा रंग ज़रूर रखें जो आपको मुस्कुराने और अच्छा महसूस कराने पर मजबूर कर दे। याद रखिए, जब आप अच्छा महसूस करती हैं, तो आप सबसे सुंदर दिखती हैं।

काश तिरंगा मेरा कफ़न होता

संजीत सोनी

भारत का तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि यह हर भारतीय के दिल की धड़कन है। यह उस मिट्टी की शान है, जिसमें हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की नींव रखी। जब कोई कहता है — 'काश तिरंगा मेरा कफ़न होता'— तो वह केवल शब्द नहीं कहता, बल्कि अपने भीतर के उस अटूट देशप्रेम को व्यक्त करता है, जो राष्ट्र के लिए जीने और मरने की प्रेरणा देता है।

तिरंगा, हमारे देश की आत्मा का प्रतीक है। इसके तीन रंग हमें जीवन के तीन महत्वपूर्ण संदेश देते हैं — केसरिया रंग हमें बलिदान, साहस और त्याग की भावना सिखाता है; सफेद रंग शांति और सत्य का संदेश देता है; और हरा रंग समृद्धि, विश्वास तथा विकास का प्रतीक है। बीच में स्थित अशोक चक्र हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में निरंतर कर्म करना ही हमारा धर्म है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसका कफ़न तिरंगा हो, तो वह चाहता है कि उसकी अंतिम यात्रा भी उसी प्रतीक के साथ हो, जो उसकी पूरी जिंदगी का गौरव बना रहा।

यह भाव केवल सैनिकों का नहीं होता, बल्कि हर उस नागरिक का होता है जो अपने देश से सच्चा प्रेम करता है। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है, तो उसे यह पता नहीं होता कि वह लौटेगा या नहीं; लेकिन उसके मन में यह गर्व जरूर होता है कि अगर वह मरेगा तो तिरंगे में लिपटा मरेगा। यही भावना उस पंक्ति में झलकती है — 'काश तिरंगा मेरा कफ़न होता'। यह वाक्य न केवल देशभक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उस उच्च विचार का भी परिचायक है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को राष्ट्र के अस्तित्व में विलीन कर देता है।

आज के युग में जब हम स्वतंत्र हैं, तब भी यह जरूरी है कि हम उस स्वतंत्रता की कीमत समझें। देश के लिए मरने वालों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से करना चाहिए। अगर हर नागरिक यह ठान ले कि वह देश की सेवा अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से करेगा, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों के लिए जिनका कफ़न तिरंगा बना।

यह पंक्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं दिखती, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी झलक सकती है — जब हम ईमानदारी से काम करें, जब हम भ्रष्टाचार का विरोध करें, जब हम पर्यावरण की रक्षा करें, जब हम शिक्षा और समानता के लिए आगे बढ़ें। यही सच्चा राष्ट्रप्रेम है।

'काश तिरंगा मेरा कफ़न होता' — यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में अमरता का भाव जगाती है। यह दर्शाती है कि मृत्यु भी गौरवशाली हो सकती है, यदि वह मातृभूमि के लिए हो। ऐसा कफ़न किसी के लिए भी सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि वह कफ़न किसी पराजय का नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक होता है — उस विजय का, जिसमें देश के प्रति समर्पण सर्वोच्च होता है।

अंततः, यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि देश की सेवा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में झलकनी चाहिए। अगर हम सभी में यह भावना जागे कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है, तब हम सच्चे अर्थों में देशभक्त बन पाएंगे।

सच में, भाग्यशाली है वह जिसने तिरंगे में जन्म लिया, और महान है वह जिसने तिरंगे में प्राण त्यागे।

काश! हर भारतीय के दिल में यही भावना जगे —'काश तिरंगा मेरा कफ़न होता'

आज़ादी की नई परिभाषा या लड़कियों के लिए नया जाल?

अनामिका पाण्डेय

आजकल रिलेशनशिप का मतलब बदल चुका है। अब सिर्फ इमोशनल कनैक्शन ही नहीं, बल्कि फिजिकल कनैक्शन भी युवाओं के लिए अहम हो गया है। खासकर जेनरेशन Z (1997-2012) के बीच हुकअप कल्चर आम बात हो गई है।

हुकअप का सीधा मतलब है- बिना किसी बंधन, बिना किसी वादे, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप। यह कभी-कभी सिर्फ एक रात तक हो सकता है या कुछ मुलाकातों तक। इसमें प्यार, शादी या भविष्य जैसी बातें जरूरी नहीं होतीं। कई लोग इसे 'फन और नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड' रिलेशन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है- क्या यह कल्चर सच में सब के लिए आसान है? क्या लड़कियों और लड़कों पर इसका असर समान है?

सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स से मिलना हुआ आसान

टिंडर, बंबल, हिंज जैसे ऐप्स ने नए लोगों से मिलने और कैजुअल डेटिंग को बेहद आसान बना दिया है। अब पसंद किसी को करना, जानना या डेट करना सिर्फ स्वाइप दूर है। कॉलेज, ऑफिस या पड़ोस तक सीमित नहीं। यही तकनीक हुकअप कल्चर को गति दे रही है।

फियर ऑफ कमिटमेंट और फ्रीडम

आज के नौजवान अक्सर शादी या सीरियस रिलेशनशिप में नहीं बंधना चाहते।

- कैरियर, पढ़ाई और पर्सनल फ्रीडम उनके लिए पहले हैं।
- ऐसे में हुकअप उन्हें आसान रास्ता लगता है—कोई जिम्मेदारी, कोई वादा नहीं।

लड़के और लड़कियां दोनों ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। पहले जहां सेक्स बड़ा टैबू था, अब यह पर्सनल चॉइस बन गया है। हुकअप साफ है—ना प्यार का झंझट, ना धोखे का डर।

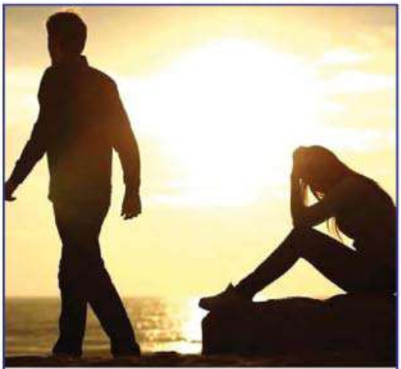

हुकअप कल्चर-आजादी या जाल?

जेन Z के लिए हुकअप कल्चर स्वतंत्रता और मज़े का प्रतीक है। यह उन लोगों के लिए आसान रास्ता है जो शादी और लॉन्ग-टर्म कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। लेकिन समाज की दोहरी सोच, लड़कियों पर इज्जत का बोझ, और फिजिकल व मानसिक रिस्क इसे आसान नहीं बनने देते। हुकअप–जैसा कि आज दिखता है–सिर्फ आज़ादी की नई परिभाषा नहीं, बल्कि सचेत और संतुलित फैसले की जरूरत भी है। हुकअप कल्चर एक साथी नहीं, विकल्प है। यह आज़ादी दे सकता है, मज़ा दे सकता है, लेकिन समझदारी और सावधानी के बिना यह अचानक दर्द और समाज की कटुता में बदल सकता है।

समाज की दोहरी मानसिकता सबसे बड़ी चुनौती है

- अगर लड़का हुकअप करता है, तो उसके दोस्त कहते हैं- 'वाह यार, मज़ा ले रहा है।'
- वही काम लड़की करे, तो तुरंत चरित्र पर सवाल उठते हैं।

एक 22 साल की सोमी का अनुभव ध्यान देने योग्य है। उसने एक डेटिंग ऐप पर मिले लड़के से हुकअप किया। दोनों की मर्जी से हुआ, लेकिन बाद में वही लड़का अपने दोस्तों के बीच उसकी बातें फैलाने लगा। शर्वरी के लिए यह अनुभव कष्टदायक और बदनाम करने वाला साबित हुआ।

ज्यादा रिस्क लड़कियों के लिए

हुकअप के बाद प्रैगनेंसी, एसटीडी या इमोशनल ट्रॉमा जैसी चुनौतियां अक्सर लड़कियों पर ही आती हैं। एक लड़की जो दृष्टि कैजुअल रिलेशन में थी और प्रैग्नेंट हो गई। लड़के ने साफ कहा, 'यह तुम्हारा फैसला है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता।' नतीजा—दृष्टि को अकेले मेडिकल अबॉर्शन और समाज की तानेबाजी झेलनी पड़ी।

इमोशनल जुड़ाव- फन के पीछे दर्द

कई बार लड़कियां कहती हैं कि हुकअप सिर्फ फन के लिए है। लेकिन इमोशंस अक्सर जुड़ ही जाते हैं। जब लड़का गायब हो जाता है—घोस्टिंग—तो लड़की अकेली रह जाती है। हुकअप कल्चर देखने में जितना कूल लगता है, लड़कियों के लिए उतना सरल नहीं। यह आज़ादी और समाज के दमन के बीच की जद्दोजहद है।

फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य के रिस्क

- **सेफ्टी की अनदेखी**- अनप्रोटेक्टेड सेक्स से प्रैगनेंसी और एसटीडी का खतरा।
- **मानसिक स्वास्थ्य**- बार-बार हुकअप करने से लड़कियों में डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
- **सामाजिक जजमेंट**- दोस्तों या समाज से दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ता है।

लोग कहते हैं, 'तुझे पता था ये रिस्की है, फिर क्यों किया?'—लेकिन सवाल है, क्या समाज की ये दोहरी मानसिकता हुकअप कल्चर को लड़कियों के लिए असंभव बनाती है?

परीक्षा का तनाव और AI: सफलता का नया डिजिटल मंत्र

Bhupender Singh,
Director -
AI, Webority
Technologies

जैसे-जैसे परीक्षाओं का समय नजदीक आता है, घर के वातावरण में एक अलग सी हलचल और चिंता दिखने लगती है। किताबों के ढेर, रात-भर जागकर पढ़ाई करना और अच्छे अंक लाने का दबाव—यह दृश्य हमारे समाज में बहुत आम है। लेकिन एक AI विशेषज्ञ के रूप में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार की परीक्षाएँ पहले जैसी नहीं होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब छात्रों के लिए एक ऐसे 'सुपर-मेंटोर' के रूप में उभर रहा है, जो न केवल पढ़ाई को आसान बनाता है, बल्कि परीक्षा के तनाव को भी कम करता है।

AI
AI
सफलता
92%

AI के साथ, हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ रटने के बजाय समझने पर जोर होगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस परीक्षा सत्र में तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और याद रखिए कि आपकी मेहनत और सही टूल्स का मेल ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा।

1. व्यक्तिगत ट्यूटरः आपकी गति, आपकी पढ़ाई

हर छात्र के सीखने की गति अलग होती है। कक्षा में शिक्षक के लिए सभी 40-50 बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो सकता है, लेकिन AI के लिए यह मुमकिन है। 'एडेप्टिव लर्निंग' (Adaptive Learning) तकनीक के माध्यम से AI टूल्स यह समझ लेते हैं कि छात्र को किस विषय में कठिनाई हो रही है। अगर किसी को गणित का कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, तो AI उसे अलग-अलग तरीकों से तब तक समझा सकता है जब तक कि छात्र उसे पूरी तरह समझ न ले। यह व्यक्तिगत ध्यान छात्र के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और 'पीछे छूट जाने' के डर को खत्म करता है।

2. स्मार्ट रिवीजन और समरी (Summary)

परीक्षा के समय सबसे बड़ी चुनौती होती है—विशाल सिलेबस को कम समय में दोहराना। AI आधारित ऐप्स अब छात्रों को लंबे अध्यायों (Chapters) के मुख्य बिंदु, फ्लैशकार्ड और संक्षिप्त नोट्स तुरंत बना कर दे सकते हैं। इससे छात्र उन विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

3. शंका समाधान (Doubt Clearing) 24×7

अक्सर छात्र रात के समय पढ़ाई करते हैं, और अगर तब कोई जटिल सवाल सामने आ जाए, तो शिक्षक उपलब्ध नहीं होते। यहाँ AI-चैटबॉट्स और टूल्स एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। छात्र अपनी शंकाएँ तुरंत पूछ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। जब मन में कोई दुविधा नहीं रहती, तो परीक्षा का तनाव अपने आप कम होने लगता है।

4. परीक्षा का डर कम करनाः मॉक टेस्ट और फीडबैक

तनाव का मुख्य कारण 'अनिश्चितता' होती है। AI टूल्स छात्रों के लिए उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर 'कस्टमाइज्ड मॉक टेस्ट' तैयार करते हैं। ये टेस्ट न केवल छात्र की तैयारी का आकलन करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी बताते हैं कि वे कहाँ गलती कर रहे हैं। जब एक छात्र बार-बार अभ्यास करता है और उसे अपनी प्रगति स्पष्ट दिखती है, तो मुख्य परीक्षा के दिन उसे घबराहट नहीं होती।

5. समय प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य

पढ़ाई के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि छात्र पर्याप्त नींद लें और आराम करें। AI आधारित शेड्यूलिंग टूल्स छात्रों को उनके दिन का सबसे प्रभावी टाइम-टेबल बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, आजकल कई ऐसे AI ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो छात्रों के तनाव स्तर को पहचानकर उन्हें ध्यान (Meditation) या छोटे ब्रेक लेने की सलाह देते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

सावधानी और संतुलन का महत्व

तकनीक का लाभ तभी है जब इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। छात्रों को यह समझना चाहिए कि AI केवल एक 'सहायक' है, वह उनकी मेहनत और मौलिक सोच का विकल्प नहीं हो सकता। उत्तरों को सीधे कॉपी करने के बजाय, समझने के लिए AIका उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है।

आने वाले समय में स्कूल और परीक्षाएँ अब बोझ नहीं लगेंगी। AI के साथ, हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ रटने के बजाय समझने पर जोर होगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस परीक्षा सत्र में तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और याद रखिए कि आपकी मेहनत और सही टूल्स का मेल ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा।

EMI का जाल

कर्ज में फंसा मिडिल क्लास

हर्षित पाण्डेय

हर महीने की पहली तारीख।

बैंक खाते में सैलरी आती है।

कुछ मिनटों में EMI कट जाती है। जो बचता है, वह क्रेडिट कार्ड में चला जाता है। और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते हैं—लोन ऐप्स के रिमाइंडर।

देश के लाखों घरों में हर महीने की पहली तारीख अब उम्मीद नहीं, डर लेकर आती है। बैंक खाते में सैलरी आती है और कुछ ही मिनटों में EMI कट जाती है। जो थोड़ा-बहुत बचता है, वह क्रेडिट कार्ड बिल में चला जाता है। इसके बाद मोबाइल फोन पर लोन ऐप्स के रिमाइंडर आने लगते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि महीना खत्म होने से पहले ही पूरी तनख्वाह साफ हो जाती है और घर चलाने के लिए हाथ में बचती है—बेचैनी। यह कहानी अंधाधुंध खर्च करने वाले लोगों की नहीं है। यह उस दौर की कहानी है, जहाँ आसान लोन ज़िंदगी को आसान बनाने के बजाय लोगों को कर्ज के जाल में जकड़ रहा है।

इमरजेंसी से आदत तक

एक समय था जब कर्ज लिया जाता था—बीमारी, शादी, पढ़ाई या किसी बड़ी आपात जरूरत के लिए। आज स्थिति उलट चुकी है। अब कर्ज ज़रूरत नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। किराया, बच्चों की फीस, मोबाइल, राशन, यहां तक कि बिजली का बिल भी कई बार कर्ज के सहारे चुकाया जा रहा है।

इस बढ़ते संकट की तस्वीर सामने रखती है एक्सपर्ट पैनल की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच देशभर के 10,000 कर्जदारों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 85% लोग अपनी मासिक आय का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ EMI चुकाने में खर्च कर रहे हैं। यानी भोजन, किराया, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फीस या इलाज जैसे ज़रूरी खर्चों से पहले ही आधी सैलरी खत्म हो जाती है।

जब कमाई नहीं, उपभोग को धर्म बना दिया गया

अमेरिका हो या भारत—आज का मीडिया, विज्ञापन तंत्र और कॉरपोरेट नैरेटिव एक ही बात पर टिका है- जो भी कमाओ, सब खर्च करो। क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ट्रैवल एजेंसियाँ और यहाँ तक कि धार्मिक आयोजनों का बाज़ार भी लोगों को लगातार खर्च करते रहने के लिए उकसा रहा है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और आक्रामक बना दिया है। हर रील, हर पोस्ट यही संदेश देती है कि ज़िंदगी कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए बनी है। यह केवल उपभोग की संस्कृति नहीं, बल्कि एक डिज़ाइन की गई अर्थव्यवस्था है।

सोचने की आज़ादी नहीं

आधुनिक बिज़नेस और इकॉनॉमिक्स को इस तरह विकसित किया गया है कि एक विशाल वर्किंग क्लास तैयार हो—जो अनपढ़ नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रीय रूप से अचेत है। इसे जीने लायक पैसा दिया जाता है, सोचने लायक नहीं। इसे सामान बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भविष्य बनाने के लिए नहीं।

उत्पादन करने वालों के ऊपर एक ऐसा वर्ग बैठा दिया गया है जो खुद कुछ बनाता नहीं, बल्कि गाइड और कंट्रोल करता है। पहले इनके पास बचा पैसा घर, गाड़ी या ठोस संपत्तियों में लगता था। आज उन्हें सिखाया जा रहा है—घर खरीदना मूर्खता है, किराए पर रहो; चीज़ें एकमुश्त लेना बेवकूफी है, श्रख्नु लो; आज खर्च करो, पैसा बाद में दो। यह सौदा दिखने में आसान है, लेकिन असल में बेहद महँगा है।

आधुनिक गुलामी का सॉफ्टवेयर

EMI सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि मुनाफे की फैक्ट्री है। हर EMI के पीछे एक लोन है, और हर लोन कई कंपनियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए टुकड़ों में बिकता है। अरबों-खरबों का कारोबार इसी कर्ज की खरीद-फरोख्त से खड़ा है। इसकी कीमत चुकाता है वही उपभोक्ता, जो सोचता है कि उसने 'सस्ता' सामान लिया है। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कुछ मैन्युफैक्चरर कैश खरीदने वालों से ज़्यादा EMI ग्राहकों को प्राथमिकता देने लगे हैं।

'आज मज़े करो' का खतरनाक मंत्र

'प्रेज़ेंट में जीयो' का सिद्धांत सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर गढ़ा हुआ धन नहीं होगा, अगर बचत नहीं होगी, अगर आपातकाल के लिए कुछ नहीं होगा— तो यह मज़ा बहुत जल्दी हताशा में बदल जाएगा। और इतिहास बताता है कि जब आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है, तो अवसाद बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, और अंततः आत्महत्याओं तक की नौबत आ जाती है। 35 से 65 हजार रुपये कमाने वाले मिडिल और लोअर मिडिल क्लास परिवार 28 से 52 हजार रुपये तक EMI भरने को मजबूर हैं। ऐसे में बजट बनाना अब समझदारी नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जद्दोजहद बन चुका है। रिपोर्ट बताती है कि करीब 40% लोग खर्च चलाने के लिए बार-बार क्रेडिट कार्ड बदलते हैं और 22% लोग दोस्तों-रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाते हैं। यह राहत अस्थायी होती है, लेकिन कर्ज का चक्र और गहरा होता जाता है।

सपनों की कुर्बानी

जब EMI समय पर नहीं चुकती, तो लोन रिकवरी एजेंट सामने आते हैं। 67% लोगों को अपमानजनक कॉल्स झेलनी पड़ीं। दिन में 50 से 100 कॉल, धमकी भरे मैसेज, और कुछ मामलों में घर-दफ्तर तक पहुंच जाना—यह अब वसूली नहीं, मानसिक उत्पीड़न है। EMI का दबाव सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, पूरी ज़िंदगी को काटता है। सर्वे में शामिल- 65% लोगों ने जरूरी खर्चों में कटौती की ,बच्चों की पढ़ाई छुड़ाना,ट्यूशन बंद करना ,इलाज टालना ,बीमा बंद करना ,खाने-पीने में कमी . हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि 16% लोगों को सैलरी एडवांस लेना पड़ा , 15% को गहने, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी . यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के टूटने की कहानी है।

सवाल सिर्फ पैसों का नहीं

यह संकट सिर्फ आर्थिक नहीं है। यह उस सिस्टम पर सवाल है जो लोगों को बिना वित्तीय समझ के कर्ज थमा रहा है। यह उस समाज पर सवाल है जहाँ सम्मान सैलरी स्लिप से जुड़ गया है। और यह उस व्यक्ति की कहानी है जो हर महीने अपनी मेहनत की कमाई को बैंक खाते में आते और तुरंत गायब होते देखता है। कर्ज अब आंकड़ों का विषय नहीं रहा। यह हर महीने कटती EMI में फंसी ज़िंदगी का नाम है।

बीमार होता मन और DATE WITH YOURSELF की अनिवार्यता

डॉ अनिल गुप्ता
फाउंडर पॉजिटिव
हेल्थ जोन
डायरेक्टर श्री गणेश
विनायक आई
हॉस्पिटल, रायपुर

आज का समय मानसिक समस्याओं का सबसे उर्वर दौर बन चुका है। चिंता (Anxiety), अवसाद (Depression), बर्नआउट, पैनिक अटैक, अकेलापन, आत्महीनता—ये अब मेडिकल शब्द भर नहीं रहे, बल्कि आम ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं डिप्रेशन कभी ढोल पीटकर नहीं आता। यह न कोई नोटिस देता है, न कोई घोषणा करता है।

यह दबे पाँव आता है—इतनी चुपचाप कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि कब उसके भीतर का उजाला धीमे-धीमे बुझने लगा। विडंबना यह है कि यह सब उस दौर में हो रहा है, जहाँ सुविधाएँ सबसे ज़्यादा हैं, कनेक्टिविटी सबसे तेज़ है, और विकल्प सबसे अधिक। फिर भी मन सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है।

मानसिक बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं?

क्योंकि हमने जीवन की गति बढ़ा ली है, लेकिन आत्मा को पीछे छोड़ दिया है। आज इंसान—

- लगातार प्रोडक्टिव रहने के दबाव में है
- सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना कर रहा है
- भावनाएँ व्यक्त करने के बजाय दबा रहा है
- और सबसे ख़तरनाक—खुद से संवाद बंद कर चुका है

हम बाहर से मुस्कुराते हैं, भीतर से थक चुके होते हैं। भीड़ में रहते हैं, लेकिन भीतर गहरा अकेलापन पलता है। यहीं से डिप्रेशन की असली एंट्री होती है।

डिप्रेशन की सबसे बड़ी चाल

डिप्रेशन आपको यह यक़ीन दिला देता है कि समस्या बाहर है— नौकरी में, रिश्तों में, हालात में, सिस्टम में। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियाँ खुद से कट जाने का परिणाम होती हैं। हम सब दूसरों के लिए समय निकालते हैं— मीटिंग, डेट, पार्टी, परिवार, समाज— लेकिन खुद के लिए कभी समय तय नहीं करते। यहीं DATE WITH YOURSELF की ज़रूरत जन्म लेती है।

DATE WITH YOURSELF – ट्रेंड नहीं, इलाज

Date with Yourself का मतलब अकेले घूमना या कॉफ़ी पीना नहीं है। यह खुद से एक ईमानदार, गहरी और कभी-कभी असहज मुलाक़ात है। एक ऐसी मुलाक़ात जहाँ आप खुद से भागते नहीं, खुद से सवाल करते हैं—

- मैं सच में खुश हूँ या बस निभा रहा हूँ?
- मैं कब से थका हूँ और क्यों?
- मेरी किन भावनाओं को मैंने 'कमज़ोरी' समझकर दबा दिया?
- मैं किस डर के कारण अपनी असली ज़रूरतों को टाल रहा हूँ?

इन सवालों से बचना आसान है, लेकिन इन्हीं सवालों से मानसिक बीमारियों की जड़ तक पहुँचा जा सकता है।

जब खुद से रिश्ता टूटता है

जब इंसान खुद से नहीं मिलता, तो वह बाहर से मान्यता माँगने लगता है। लाइक्स, अप्रूवल, तारीफ़, सफलता— यही उसकी आत्म-मूल्य की परिभाषा बन जाती है। और जिस दिन यह सब कम होता है, मन भीतर से टूटने लगता है। आज की बढ़ती Anxiety और Depression इसी टूटी हुई Self-worth की कहानी है।

खुद से मिलने की प्रक्रिया

Date with Yourself कोई एक दिन का इवेंट नहीं, यह एक निरंतर अभ्यास है—

1. खामोशी को जगह दीजिए

हर खाली पल में मोबाइल मत भरिए। खामोशी डराती है क्योंकि वहीं दबे सच बोलते हैं।

2. भावनाओं को नाम दीजिए

हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती। कभी वह थकान है, कभी निराशा, कभी गुस्सा। भावना को नाम देने से उसका बोझ हल्का होता है।

3. परफेक्शन का बोझ उतारिए

आप इंसान हैं, मशीन नहीं। हर दिन बेहतर होना ज़रूरी नहीं— कभी-कभी बस ज़िंदा रहना भी पर्याप्त है।

4. शरीर की भाषा समझिए

नींद, भूख, थकान— ये शिकायतें नहीं, चेतावनियाँ हैं।

लड़ाई नहीं, संवाद ज़रूरी है

डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों से लड़ने के बजाय उनसे संवाद करना ज़रूरी है। ये आपके दुश्मन नहीं, ये संकेत हैं कि आपने खुद को बहुत देर तक नज़रअंदाज़ किया है। DATE WITH YOURSELF उसी उपेक्षा का जवाब है।

यह बात सच है कि डिप्रेशन दबे पाँव आता है,लेकिन अगर आप रोज़ खुद से मिलते रहें, तो उसके पास टिकने की जगह नहीं बचती। याद रखिए— दुनिया से रिश्ता निभाने से पहले खुद से रिश्ता ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान खुद का नहीं हुआ, वह सारी दुनिया पाकर भी अंदर से खाली ही रहता है।

मन का युद्ध भूमि

NLP

।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ।।

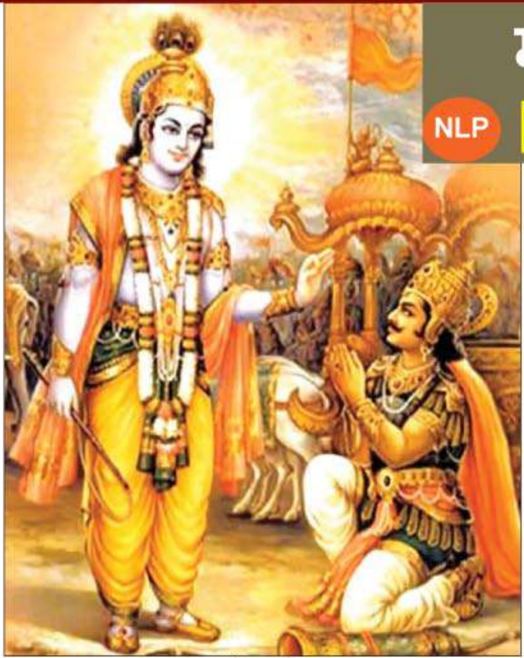

नरेन्द्र पाण्डेय

गतांक से आगे

श्लोक 7

अब तक दुर्योधन पांडवों की सेना की ताक़त गिनाता रहा। पर सातवें श्लोक में अचानक उसे याद आता है – 'हमारी भी तो सेना है!'

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते॥

'अब हमारी सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं को जानो - आप (द्रोण), भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति। पहले छह श्लोकों तक वह पांडवों की ताकत गिनता रहा। अब जैसे उसे याद आया -'हमारी सेना भी तो है!'

'अस्माकं तु' - यह दिखाता है कि वह पहले ही पांडवों से प्रभावित हो चुका है। यह उस इंसान की भाषा है जो दूसरों की ताक़त देखकर भीतर से हल्का दब चुका होता है। 'मम सैन्यस्य' (मेरी सेना) कहकर वह अधिकार दिखाता है, पर उसमें आत्मविश्वास नहीं है। पर यह Ownership में डर छिपा है, शक्ति नहीं। जब व्यक्ति authority दिखाता है, पर भीतर से उसे उस authority पर भरोसा नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे कोई बोले- 'ये मेरी टीम है, हाँ, मेरी!' – आवाज़ में आग्रह ज़्यादा होता है, आत्मविश्वास कम। यह वही मनोवैज्ञानिक क्षण है जब कोई इंसान अपने मुकाबले वाले की ताक़त देखकर भीतर ही भीतर कमजोर पड़ जाता है, और फिर अचानक खुद को याद दिलाता है – 'मेरे पास भी कुछ है!' पर यह याद दिलाना आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि सांत्वना से भरा होता है।

जब कोई इंसान अपने मुकाबले वाले की ताक़त देखकर भीतर ही भीतर कमजोर पड़ जाता है, और फिर अचानक खुद को याद दिलाता है – 'मेरे पास भी कुछ है!' पर यह याद दिलाना आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि सांत्वना से भरा होता है।

'संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते' - केवल नाम बता रहा हूँ मैं उन्हें बस नाम से तुम्हें बता रहा हूँ। यानी वह अपने योद्धाओं की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा,

सिर्फ़ नाम भर गिनाने वाला है – जैसे उसे खुद भरोसा न हो कि वे युद्ध में क्या करेंगे। यह एक मनःस्थिति की प्रतीक भाषा है-

जब व्यक्ति किसी टीम का लीडर होता है, पर भीतर से उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा नहीं होता – तब वह बातों से डिफेंड करने लगता है, प्रेजेंट नहीं करता।

सोचिए, कोई मैनेजर कहे-

'हाँ, हमारी टीम में भी कुछ लोग हैं – अमर, नील, और रजत, बस, नाम याद रखिए।' यह Team का परिचय नहीं, बल्कि संकोच और संदेह से भरी 'Formal Compliance' है। वो टीम का परिचय नहीं दे रहा,

बल्कि अपनी असुरक्षा छिपा रहा है। क्योंकि जो नेता अपनी टीम पर भरोसा करता है, वो नाम नहीं गिनाता – वो कहता है – 'हम तैयार हैं।'

अब ज़रा ध्यान दीजिए – दुर्योधन पांडवों के योद्धाओं को 'महारथी, पराक्रमी, शक्तिशाली' कहता है,

पर अपने योद्धाओं को बस 'नाम' से पुकारता है , अपनी सेना के लिए कोई विशेषण नहीं दिया। कोई गौरव नहीं । यह एक nconscious Value Leak है – जहाँ भाषा व्यक्ति की भीतर की सच्चाई खोल देती है। कोई गौरव नहीं। यह श्लोक दर्शाता है कि बातें चाहे जितनी सामर्थ्य वाली लगें, अगर शब्दों में आत्मविश्वास न हो – तो मन की कमजोरी ज़ाहिर हो ही जाती है। **क्रमशः**

भगवद्गीता - NLP

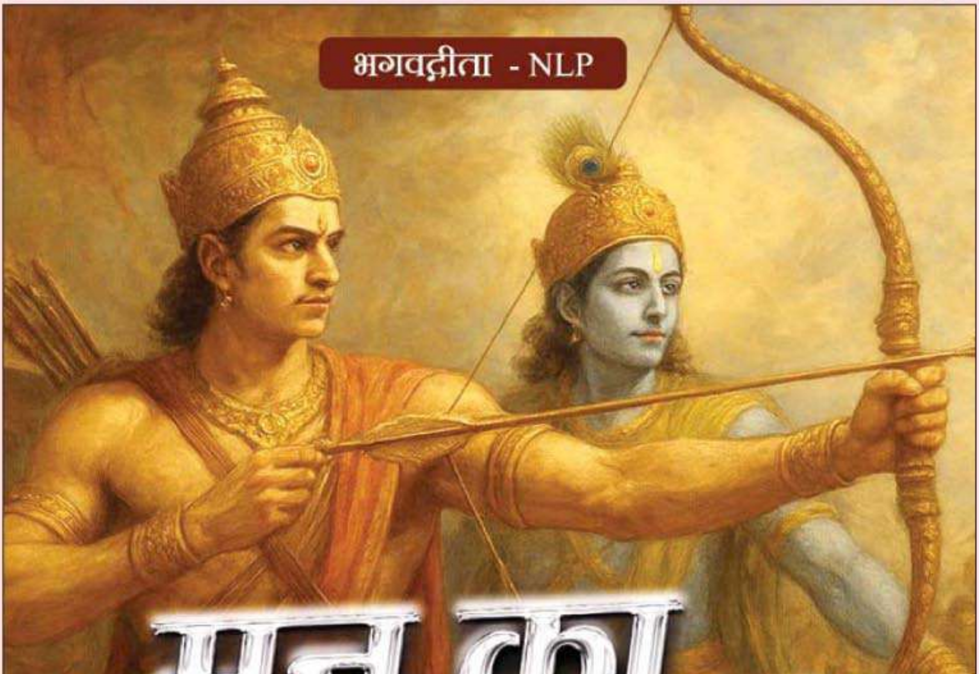

मन का युद्धभूमि

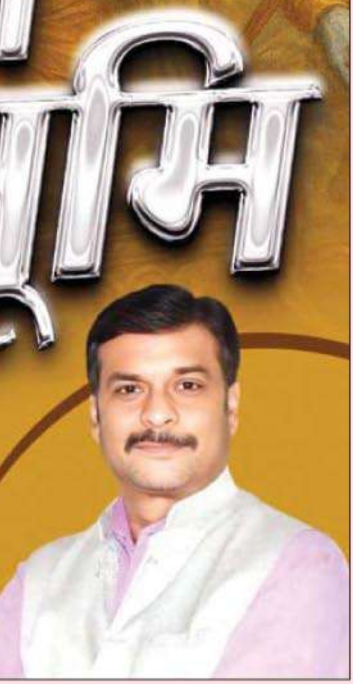

नरेन्द्र पाण्डेय

www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic Health Care System

Unique Wellbeing Center

Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing

MIND BRAIN BODY SOUL
M.B.B.S

❶ Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-

Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.

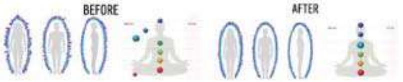

❷ Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -

Personality Analysis Body Type, Mind Type, Energy Type.

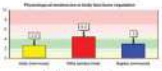

VATA , PITTA , KAPHA

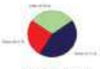

SATTVA, RAJAS, TAMAS

PRANA, TEJAS, OJAS

7 Dhatus - Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asthi, Majja, Shukra

5 Element - Ether, Air, Fire, Water , Earth

Veda Pulse

❸ Life Style Clinic

Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.

❹ Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.

डॉ. रमेश सी. नायर
(आयुर्वेदाचार्य एवं पंचकर्म विशेषज्ञ)

❺ Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.

LIFE
COACHING

❻ Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.

Get In Touch
9109185028, 9109185025

A-41, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com